



बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों को ढूंढ ढूंढ कर भगाया जा रहा है

पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद अब वह दौर शुरू हो चुका है, जिसका इंतजार लंबे समय से राज्य की जनता कर रही थी। मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी के नेतृत्व में बंगाल सरकार ने अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ जिस सख्त अभियान की शुरुआत की है, उसने सीमा पार बैठे घुसपैठियों और उनके संरक्षकों में भारी दहशत फैला दी है। डिटेक्ट-डिलीट-डिपोर्ट नीति के तहत बंगाल सरकार अब हर उस व्यक्ति की पहचान कर रही है जो अवैध तरीके से भारत में घुसकर यहां के संसाधनों पर कब्जा जमाए बैठा था। सरकार का साफ संदेश है कि भारत की जमीन अब घुसपैठियों की शरणस्थली नहीं बनेगी।

उत्तर 24 परगना के स्वरूपनगर स्थित हाकिमपुर जांच चौकी पर जो दृश्य दिखाई दिया, उसने वर्षों से चल रहे अवैध घुसपैठ के पूरे खेल को उजागर कर दिया। सैकड़ों बांग्लादेशी मुसलमान पुरुष, महिलाएं और बच्चे बैग, कंबल और टूट्टीयों के साथ सीमा पर जमा हो गए ताकि गिरफ्तारी और हिरासत से पहले किसी तरह वापस बांग्लादेश पहुंच सकें। यह वही लोग हैं जो वर्षों से बंगाल के अलग-अलग इलाकों में बिना किसी वैध दस्तावेज के रह रहे थे और



स्थानीय संसाधनों पर बोझ बने हुए थे।

मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि जो अवैध तरीके से भारत में रह रहे हैं, वे तुरंत वापस लौट जाएं, अन्यथा सरकार अपना काम करेगी। उनका यह कठोर रुख ही आज बंगाल की जनता में विश्वास पैदा कर रहा है। वर्षों तक तुष्टिकरण की राजनीति करने वाली ताकतों ने घुसपैठ को नजरअंदाज किया, लेकिन अब पहली बार राज्य सरकार खुलकर राष्ट्रीय सुरक्षा के पक्ष में खड़ी दिखाई दे रही है। शुभेन्दु अधिकारी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि बंगाल की जनता के भोजन, रोजगार और संसाधनों पर पहला अधिकार भारतीय नागरिकों का है, न कि अवैध घुसपैठियों का।

राज्य सरकार ने हर जिले में होलिंग सेंटर बनाने की प्रक्रिया तेज कर दी है। स्वरूपनगर क्षेत्र में पहले से तीन होलिंग सेंटर संचालित हो रहे हैं, जहां करीब तीन सौ पचास घुसपैठियों को रखा गया है। सिलिगुड़ी, मादीगाड़ा और नक्सलबाड़ी क्षेत्र में भी नया होलिंग सेंटर बनाया जा रहा है। सीमा क्षेत्रों में निगरानी कई गुना बढ़ा दी गई है। पुलिस, सीमा सुरक्षा बल और प्रशासनिक एजेंसियां लगातार

दस्तावेजों की जांच कर रही हैं ताकि कोई भी अवैध व्यक्ति बच न सके।

हाकिमपुर में पहुंचे कई लोगों ने खुद स्वीकार किया कि वह वर्षों से बिना दस्तावेजों के बंगाल में रह रहे थे। कुछ ने यह भी माना कि यदि पिछली सरकार सत्ता में बनी रहती तो उन्हें कभी लौटने की जरूरत नहीं पड़ती। यही बयान यह साबित करता है कि वर्षों तक राजनीतिक संरक्षण के कारण बंगाल में अवैध घुसपैठ को बढ़ावा मिलता रहा। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। भाजपा सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि बंगाल को अवैध घुसपैठ से मुक्त करना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। दस्तावेज जांच, सीमा

निगरानी और होलिंग सेंटरों की तैयारी ने उन लोगों की नींद उड़ा दी है जो वर्षों से भारत में छिपकर रह रहे थे। अब उन्हें समझ आ चुका है कि भारत की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वालों के लिए यहां कोई जगह नहीं बची है।

हम आपको याद दिला दें कि तृणमूल कांग्रेस वर्षों तक यह दावा करती रही कि बंगाल में बड़े पैमाने पर घुसपैठ नहीं होती। लेकिन आज सीमा पर लगी कतारें खुद सच्चाई बयान कर रही हैं। जिन लोगों ने बंगाल को वोट बैंक की जनता अब सुरक्षित सीमाएं और सख्त प्रशासन चाहती है।उधर, इस पूरे घटनाक्रम के बीच भारत-बांग्लादेश सीमा की ओर अधिक सुरक्षित बनाने के लिए कई नए प्रस्तावों पर भी चर्चा चल रही है। नदी और दलदली इलाकों में जहां बाड़ लगाना कठिन है, वहां मगरमच्छ और जहरीले सांप जैसे खतरनाक जीवों को तैनात करने की संभावना पर विचार करने की खबरें हैं। बताया जा रहा है कि सीमा सुरक्षा बल ने इन संवेदनशील इलाकों में प्राकृतिक अवरोध खड़े करने की व्यवहारिकता पर अध्ययन शुरू किया है।



रायपुर। वन मंत्री केदार कश्यप ने आज दंतेवाड़ा प्रवास के दौरान शक्तिपीठ प्रसिद्ध मां दंतेश्वरी मंदिर पहुंचकर विधि-विधान से पूजा-अर्चना की। उन्होंने मां दंतेश्वरी के चरणों में शीश नवाकर समस्त प्रदेशवासियों के जीवन में सुख-समृद्धि, शांति और उन्नति की कामना की। वन मंत्री श्री कश्यप की गरिमामयी उपस्थिति के दौरान पूरा मंदिर परिसर श्रद्धा, भक्ति और जयकारों के अनूठे माहौल से सराबोर रहा।

प्रमुख समाचार

पीएम मोदी ने सावरकर और एनटी रामाराव को दी श्रद्धांजलि

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को विनायक दामोदर सावरकर की 143वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि सावरकर का साहस और देशभक्ति हमेशा लोगों को प्रेरित करती रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि वीर सावरकर को उनकी जयंती पर याद कर रहा हूं। उनका साहस और देशभक्ति हमेशा लोगों को प्रेरित करेगी। उनकी बुद्धिमत्ता और सामाजिक सुधारों पर दिया गया जोर भी उल्लेखनीय है। साथ ही पीएम ने तेलुगु देशम पार्टी के संस्थापक एनटी रामाराव की 103वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि गरीबों और वंचितों के सम्मान के लिए एनटीआर की जनकल्याण और सुशासन के प्रति प्रतिबद्धता हमेशा याद रखी जाएगी। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि महान एनटीआर गुरु को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि। जनकल्याण और सुशासन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने गरीबों और वंचितों को सम्मान दिलाया।

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव विपक्ष के सामने नई चुनौती

भाजपा की हैट्रिक को कैसे रोक पाएंगी सपा-कांग्रेस

- विपक्ष की स्वरूपरणीति को सुप्रीम कोर्ट से झटका
- भाजपा विकास और कानून व्यवस्था पर तीसरी जीत का लक्ष्य
- सपा-कांग्रेस को यूपी चुनाव में नए मुद्दे की तलाश

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अब कुछ महीनों का ही समय बचा है। लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी की आस में भाजपा विकास और मजबूत कानून व्यवस्था का मांडल जनता के बीच ले जाने की तैयारी में है, तो विपक्ष की कोशिश है कि कोई मुद्दा खड़ा कर भागवा दल का विजय रथ रोका जाए। जातीय समीकरणों के सहारे भाजपा को

घेरने की विपक्ष की तैयारी भले ही हो, लेकिन फिलहाल मुद्दे के नाम पर उसके हाथ खाली दिखाई दे रहे हैं।

सपा और कांग्रेस अब तक मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को ही सरकार के खिलाफ हथियार के रूप में धार देने के प्रयास में जुटी थी, लेकिन बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में इसके विफल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने भी एसआईआर के वार की धार कुंद करने की परिस्थितियां बना दी हैं। अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं।

भाजपा को मिली 400 सीटें

यहां विपक्ष का उत्साहित होना स्वाभाविक है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में कुछ



भाजपा नेताओं के बयानों को ही आधार बनाकर सपा आरक्षण को मुद्दा बनाते हुए यह नैरेटिव बनाने में सफल रही कि भाजपा को 400 सीटें मिल गईं तो संविधान बदलकर आरक्षण खत्म कर देगी। फिर जातीय बिसात भी सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अच्छी बिछाई।

जीत मिली। इसके बाद देशभर के विपक्षी दलों ने एसआईआर को मुद्दा बनाने का प्रयास शुरू कर दिया। आरोप लगाए कि भाजपा और चुनाव आयोग की मिलीभगत से मददाताओं के नाम सूची से हटाए जा रहे हैं। चूंकि, धरातल में जनता को एसआईआर में कोई खामी दिखाई नहीं दी तो सबसे पहले बिहार और फिर पश्चिम

आखिरकार भाजपा जीती और धीरे-धीरे आरक्षण में बदलाव का ध्रमजाल टूटने के बाद कई राज्यों में भाजपा को अप्रत्याशित विपक्ष का संगठन मजबूत है, इसलिए एसआईआर का मुद्दा निर्णायक होगा। यही वजह है कि कांग्रेस ने एसआईआर योद्धा नियुक्त कर दिए। इसकी निगरानी के लिए प्रदेश और जिला स्तर पर कमेटि बना दी। वहीं, सपा ने बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं

बंगाल में भी विपक्ष को इस मुद्दे से कोई लाभ नहीं हुआ।

एसआईआर पर दांव खेलने की तैयारी

इसके बावजूद सपा और कांग्रेस को विश्वास था कि वह उत्तर प्रदेश में अपनी रणनीति से इस मुद्दे को जनता के बीच खड़ा करने में सफल रहेंगी। सैफई परिवार से जुड़े सपा के एक राष्ट्रीय नेता ने दावा किया कि बिहार में भले सफलता नहीं मिली, लेकिन यूपी में सपा का संगठन मजबूत है, इसलिए एसआईआर का मुद्दा निर्णायक होगा। यही वजह है कि कांग्रेस ने एसआईआर योद्धा नियुक्त कर दिए। इसकी निगरानी के लिए प्रदेश और जिला स्तर पर कमेटि बना दी।

वहीं, सपा ने बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं

को एसआईआर की निगरानी पर लगा दिया और सपा प्रमुख लगातार इससे जुड़ी शिकायतों को ही इंटरनेट मीडिया पर प्रचारित-प्रसारित करने लगे। इसके साथ-साथ बिजली के स्मार्ट मीटर, बिजली संकट सहित अन्य मुद्दों पर भी सपा मुखर रही, लेकिन रणनीतिक तौर पर प्राथमिकता में एसआईआर ही रहा, लेकिन जिस तरह से एसआईआर को लक्ष्मी भंडार की प्रक्रिया को सही ठहरा दिया है, उसने विपक्ष के एजेंडे को करारा झटका दिया है।

निस्संदेह विपक्ष अभी भी इससे जुड़े विषयों को उठाने का प्रयास करता रहेगा, लेकिन काट में भाजपा के तर्कों को अब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का मजबूत सहारा मिलेगा। ऐसे में विपक्ष के सामने सरकार के विरुद्ध नया मुद्दा खड़ा करने की चुनौती जरूर होगी।

येरने की विपक्ष की तैयारी भले ही हो, लेकिन फिलहाल मुद्दे के नाम पर उसके हाथ खाली दिखाई दे रहे हैं।

सपा और कांग्रेस अब तक मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को ही सरकार के खिलाफ हथियार के रूप में धार देने के प्रयास में जुटी थी, लेकिन बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में इसके विफल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने भी एसआईआर के वार की धार कुंद करने की परिस्थितियां बना दी हैं। अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं।

भाजपा को मिली 400 सीटें

यहां विपक्ष का उत्साहित होना स्वाभाविक है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में कुछ

बूथ में घुसकर तोड़फोड़ करने वाले आरोपी की याचिका खारिज



बिलासपुर। पोलिंग बूथ में घुसकर तोड़फोड़ करने व चुनाव सामग्री लूटने का प्रयास करने पर प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984 के सेक्शन 3 और छत्तीसगढ़ ड्कू डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984 के तहत एफआईअर दर्ज हुई थी। इस एफआईआर को रद्द कराने हाईकोर्ट में पेश याचिका अवकाशकालीन डीबी ने खारिज

कर दी है।

दरअसल, 5 मार्च 2025 को बलरामपुर जिला के रामचंद्रपुर में पंचायत चुनाव के दौरान बूथ नंबर 115 गांव आरोपी मोहम्मद बक्स 100-150 लोगों के साथ वहां आया, और पोलिंग बूथ सेंटर में घुसकर गालियां देते हुए बूथ सेंटर के दो ताले तोड़ दिए, चुनाव का सामान छीनने की कोशिश कर चुनाव ड्यूटी पर मौजूद दूसरे

सरकारी अधिकारियों की ऑफिशियल ड्यूटी में रुकावट डाली। पोलिंग बूथ अधिकारी खिलेश्वर राम की शिकायत पर पुलिस ने जांच बाद आरोपी मोहम्मद बक्स सहित अन्य के खिलाफ अपराध दर्ज किया। जिसे रद्द करने हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी। कोर्ट ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद याचिका रद्द कर दी है।

बीजापुर के दूरस्थ वनांचल में कुपोषण मुक्त अभियान की बड़ी सफलता

- महिला एवं बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य अमले और आंगनबाड़ी टीम के समन्वित प्रयासों से कुपोषण को मात देकर सामान्य श्रेणी में लौटा ढाई वर्षीय अरुण**

बीजापुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा संचालित कुपोषण मुक्त छत्तीसगढ़ के संकल्प को बीजापुर जिले में लगातार जमीन पर उतारा जा रहा है।

महिला एवं बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग तथा जिला प्रशासन के समन्वित प्रयासों से अब दूरस्थ अंचलों में भी बच्चों के स्वास्थ्य में सकारात्मक बदलाव देखने को



मिल रहा है। इसी का प्रेरणादायी उदाहरण है बीजापुर जिले के गंगालूर क्षेत्र के आंगनबाड़ी केंद्र कोटिया पारा का ढाई वर्षीय बालक अरुण हेमला, जिसने सतत देखभाल, सही पोषण और सामुदायिक सहयोग से कुपोषण को मात देकर सामान्य श्रेणी में वापसी की है। यह कहानी केवल

एक बच्चे के स्वस्थ होने की नहीं, बल्कि शासन की योजनाओं, विभागीय प्रतिबद्धता और सामुदायिक सहभागिता की जीवंत मिसाल है। अरुण हेमला, पिता मंगू हेमला एवं माता शर्मीला हेमला का जन्म 21 दिसंबर 2023 को हुआ था। जन्म के समय उसका वजन 2.500 किलोग्राम था। बार-बार बीमार पड़ने तथा घर में पर्याप्त भोजन नहीं कर पाने के कारण उसका वजन लगातार कम बना रहा। अप्रैल 2025 में स्थिति गंभीर होने पर उसे पोषण पुनर्वास केंद्र बीजापुर में भर्ती कराया गया, जहां भर्ती के समय उसका वजन मात्र 8.600 किलोग्राम था, जो उसकी उम्र के अनुसार अत्यंत कम माना गया।

पोषण पुनर्वास केंद्र से डिस्चार्ज होने के बाद महिला एवं बाल विकास विभाग की टीम ने अरुण के स्वास्थ्य सुधार को

मिशन की तरह लिया। पर्यवेक्षक श्रीमती उषा वर्मा के मार्गदर्शन में मुमोता सोरी, सहायिका श्रीमती सोनिया माज्जी, मितानिन श्रीमती देवली वाचम एवं ए.एन.एम. श्रीमती शोभा किरण मिंज ने लगातार समन्वित प्रयास किए। टीम ने घर-घर जाकर न केवल बच्चे की निगरानी की, बल्कि परिवार को पोषण, स्वच्छता और संतुलित आहार के प्रति जागरूक भी किया।

निरीक्षण के दौरान टीम ने पाया कि अरुण घर पर अकेले भोजन नहीं करता था, लेकिन आंगनबाड़ी केंद्र में अन्य बच्चों के साथ बैठकर पूरा भोजन कर लेता था। इसके बाद माता-पिता को नियमित रूप से बच्चे को आंगनबाड़ी केंद्र भेजने के लिए प्रेरित किया गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा हर सप्ताह बच्चे का

वजन लिया गया तथा परिवार को भोजन की थाली में अनाज, दाल, सब्जी और फल जैसे चार रंगों को शामिल करने की जानकारी दी गई। केंद्र में प्रतिदिन गर्म पका भोजन एवं रेडी-टू-ईट पोषण आहार उपलब्ध कराया गया। साथ ही मितानिन द्वारा दस्त एवं निमोनिया जैसी बीमारियों से बचाव के उपाय भी बताए गए। लगातार 13 महीनों तक चले इन प्रयासों का सकारात्मक परिणाम सामने आया और मई 2026 में अरुण का वजन बढ़कर 10.600 किलोग्राम पहुंच गया। अब वह अपनी उम्र के अनुसार सामान्य श्रेणी में शामिल हो चुका है। उसके चेहरे पर लौटी मुस्कान और आंखों की चमक इस बात का प्रमाण है कि सही समय पर सही देखभाल से कुपोषण जैसी समस्या पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकता है।

संयंत्र क्षेत्रों के स्कूलों में स्थापित होंगे स्मार्ट डिजिटल वलासरूम



- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य-4 के अनुरूप सेल की सीएसआर पहल**

भिलाई। भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के अधीन देश की अग्रणी महारत्न इस्पात उत्पादक कंपनी, स्टील ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और शिक्षा मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, एड्सिल (इंडिया) लिमिटेड के मध्य कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नई दिल्ली में संपन्न हुए इस रणनीतिक समझौते का मुख्य उद्देश्य सेल के विभिन्न संयंत्र एवं परिचालन क्षेत्रों के आसपास स्थित विद्यालयों में अत्याधुनिक स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम की स्थापना करना है। इस दूरदर्शी पहल के माध्यम से औद्योगिक अंचलों में रहने वाले छात्र-छात्राओं को आधुनिक और तकनीकी रूप से समृद्ध शिक्षण माहौल उपलब्ध कराया जाएगा।

यह द्विपक्षीय सहयोग देश में समावेशी शिक्षा के ढांचे को मजबूत करने और दूरदराज के क्षेत्रों में शैक्षणिक परिणामों (लर्निंग आउटकम्स) को बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह पूरी परियोजना सीधे तौर पर भारत सरकार की %राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के दिशानिर्देशों और संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य-4 के वैश्विक मानकों के अनुरूप तैयार की गई है। इसके माध्यम से समाज के हर वर्ग के लिए न्यायसंगत, गुणवत्तापूर्ण और समान शिक्षा के अवसर सुनिश्चित किए जा रहे हैं, ताकि डिजिटल विभाजन को पाटकर युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार किया जा सके। इस गरिमामयी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के अवसर पर सेल के निदेशक (कार्मिक), श्री के. के. सिंह विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान सेल और एड्सिल दोनों ही संगठनों में रहने वाले वरिष्ठ अधिकारियों और तकनीकी विशेषज्ञों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।

विधायक-नायब तहसीलदार विवाद में दोनों पक्षों पर एफआईआर दर्ज

अंबिकापुर। सरगुजा जिले के सीतापुर विधानसभा क्षेत्र में विधायक और नायब तहसीलदार के बीच विवाद का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। एक ओर जहां राजापुर उप तहसील में पदस्थ नायब तहसीलदार तुषार मानिकपुरी की शिकायत पर सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो और उनके समर्थकों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है, वहीं दूसरी ओर विधायक की बहन की शिकायत पर नायब तहसीलदार के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ है। जानकारी के अनुसार 27 मई को शाम राजापुर तहसील तिराहे के पास कथित विवाद के दौरान नायब तहसीलदार तुषार मानिकपुरी के साथ मारपीट और शासकीय कार्य में बाधा



पहुंचाने का आरोप लगाया गया। नायब तहसीलदार ने अपनी शिकायत में कहा कि विधायक रामकुमार टोप्पो, यूसुफ, नाजिम रजा, पंकज गुप्ता समेत

10ड्कू12 लोगों ने शोध क्षमता प्रमाण पत्र पर तत्काल हस्ताक्षर करने का दबाव बनाया। मना करने पर अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए मारपीट की गई और उन्हें जमीन पर गिरा दिया गया। घटना के दौरान एसडीएम सीतापुर फागुन सिन्हा भी मौजूद थे। शिकायत में कहा गया कि एसडीएम ने बीच-बचाव कर स्थिति को संभाला, अन्यथा बड़ी घटना हो सकती थी। कोतवाली पुलिस ने नायब तहसीलदार की शिकायत पर विधायक रामकुमार टोप्पो सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि प्रकरण गैर-जमानती धाराओं के अंतर्गत दर्ज किया गया है। विधायक रामकुमार टोप्पो की चचेरी बहन सीमा धनकी की शिकायत पर

नायब तहसीलदार तुषार मानिकपुरी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। महिला ने आरोप लगाया है कि तहसील कार्यालय में उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया, जातिसूचक गाली-गलौज की गई तथा धक्का-मुक्की कर कार्यालय से बाहर निकाला गया। महिला की शिकायत पर पुलिस ने नायब तहसीलदार के खिलाफ बीएनएस की धाराओं के तहत जमानती धाराओं में मामला दर्ज किया है। इधर दोनों पक्षों पर एफआईआर दर्ज होने के बाद जिले में राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। मामले को लेकर भाजपा और प्रशासनिक अमले में भी चर्चा का माहौल बना हुआ है। पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच में जुटी हुई है।

कोरबा में चांदी चोरी मामला : व्यापारी का आरोप, पुलिस ने दर्ज नहीं की रिपोर्ट

कोरबा। मुंबई से छत्तीसगढ़ में चांदी के जेवरताओं की स्पन्डाई करने वाले व्यापारी संजय कुमार बाहेती पुलिस और केंद्रीय जीएसटी अधिकारियों की मनमानी से परेशान हैं। कोरबा जिले के बांगो थाना क्षेत्र में 13 मई की रात बस में सफर के दौरान उनके 10 किलो चांदी के जेवर चोरी हो गए।

हैरानी की बात है कि कोरबा पुलिस चोरी की रिपोर्ट लिखने से इनकार कर रही है, जबकि चोरी से बची 12 किलो 377 ग्राम चांदी जीएसटी कार्यालय में फंसी हुई है। मुंबई निवासी संजय 23 किलो चांदी के जेवर लेकर 13

मई को अंबिकापुर से रायपुर जा रहे थे। बांगो थाना क्षेत्र के एक होटल पर रात करीब 1 बजे बस रुकी। संजय लघुशंका के लिए नीचे उतरे और तीन बैग सीट पर छोड़ दिए।

लौटे तो 10 किलो चांदी वाले दो बैग गायब थे। संजय का आरोप है कि बस ड्राइवर ने उन्हें गुमराह किया और किसी से बात नहीं करने दी।

जब उन्होंने बांगो थाने में शिकायत की तो पुलिस ने उल्टा उन पर ही शक जताया। पुलिस ने कहा कि आपके पास कोई माल नहीं था, और था भी तो चोरी आपने खुद की है।

तेंदूपता गोदाम आग मामले में हटाए गए डीएफओ, 10 करोड़ का नुकसान

बीजापुर। बीजापुर के ईटपाल स्थित अताउर्रहमान के निजी तेंदूपता गोदाम में सोमवार को भीषण आग लग गई। इस घटना में लगभग 18 हजार मानक बोरा तेंदूपत्ता जल गया। इससे करीब 10 करोड़ रुपये के नुकसान का अनुमान है। इस मामले में वन विभाग ने त्वरित कार्रवाई की है। डीएफओ रमेश कुमार जांगड़े को पद से हटाकर मुख्यालय अटेंच कर दिया गया है। उनकी जगह आईएफएस जादव सागर रामचंद्र को बीजापुर का नया वनमंडलाधिकारी बनाया गया है।

हालांकि, अब गोदाम की निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था संभालने वाले अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि



विभागीय हलकों और स्थानीय नागरिकों में चर्चा है कि अन्य जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। तेंदूपत्ता भंडारण की निगरानी और सुरक्षा की जवाबदेही सीधे तौर पर गोदाम प्रभारी और निरीक्षणकर्ता अधिकारियों की मानी जाती है। इतनी बड़ी आगजनी की घटना कई गंभीर सवाल खड़े करती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि

पर्याप्त निगरानी से करोड़ों रुपये का तेंदूपत्ता बचाया जा सकता था।

तेंदूपत्ता के सुरक्षित भंडारण के लिए कई अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई थी। इनमें वन परिक्षेत्र अधिकारी दीक्षा वर्मन और सुभांश मांझी शामिल थे। गोदाम प्रभारी दीनानाथ गोसाईं और उपवन क्षेत्रपाल डमरू धर बघेल भी तैनात थे। इन सभी को

गोदाम की सुरक्षा, रखरखाव और आग से बचाव के इंतजाम सुनिश्चित करने थे। इसके बावजूद आग लगने से उनकी भूमिका पर सदेह गहरा गया है।

स्थानीय नागरिकों का कहना है कि केवल डीएफओ पर कार्रवाई कर विभाग अन्य जिम्मेदारों को बचा रहा है। मौके की सुरक्षा और गोदाम संचालन से जुड़े कर्मचारियों की जवाबदेही अब तक तय नहीं हुई है। नागरिकों ने पूरे मामले की उच्चस्तरीय और निष्पक्ष जांच की मांग की है। वे चाहते हैं कि वास्तविक जिम्मेदारों की पहचान कर उन पर भी कार्रवाई हो। निरीक्षणकर्ता अधिकारियों की भूमिका पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है।

छत्तीसगढ़

प्रमुख समाचार

पत्रकार को मिला 20 तोला सोना व नगद पुलिस को सौंपा

बेमेतरा। जिले में ईमानदारी और मानवीय संवेदनाओं की एक प्रेरणादायक मिसाल सामने आई है। स्थानीय निवासी एवं वरिष्ठ पत्रकार आनंद साहू ने लावारिस हालत में मिले लाखों रुपये के जेवर और नगदी से भरे बैग को पूरी ईमानदारी के साथ पुलिस के हवाले किया। इस घटनाका पूरे जिले में उनकी जमकर प्रशंसा हो रही है। जानकारी के मुताबिक, आनंद साहू रोज की तरह मॉनिंग वॉक पर निकले थे। इसी दौरान शहर के सिग्नल चौक स्थित एक दुकान के पास उन्हें काले रंग का बैग लावारिस हालत में पड़ा मिला। बैग की जांच करने पर उसमें सोने के आभूषण और करीब 40 हजार रुपये नकद मिले। आनंद साहू ने बिना देर किए बैग को बेमेतरा सिटी कोतवाली थाना पहुंचाकर पुलिस को सौंप दिया। जांच में पता चला कि यह बैग ग्राम अमोरा निवासी ज्वेलरी निर्माता विजय कुमार सोनी का था। बताया जा रहा कि वह रात में दुकान बंद कर अपने भाई के पास गए थे, तभी रास्ते में बैग गिर गया था। बैग में लगभग 20 तोला सोना और 40 हजार रुपये नगद मौजूद थे।

गरीबों के हटाए ठेले लेकिन भू-माफियाओं पर मेहरबानी

खैरागढ़। खैरागढ़ शहर में प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर बड़ा विरोधाभास सामने आया है। एक ओर न्यायालय परिसर के सामने सड़क किनारे वर्षों से रोजी-रोटी चला रहे छोटे ठेले और खोमचे हटाने के लिए प्रशासनिक अमला सक्रिय दिखाई दिया, वहीं ठीक उसी परिसर के सामने सरकारी जमीन को 22 हिस्सों में बांटकर की गई कथित अवैध प्लान्टिंग और कब्जों पर आठ महीने बाद भी कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हो सकी है। इससे प्रशासन की कार्यशैली और कार्रवाई की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। मामला एडवर्ड पार्क के सामने न्यायालय से लगी नजूल भूमिका है। तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक और पंचवारी की संयुक्त जांच में यह स्पष्ट रूप से सामने आया कि नजूल प्लॉट नंबर 114 एवं 115, मूल खसरा नंबर 169 की जमीन को बिना वैधानिक अनुमति 22 टुकड़ों में विभाजित कर अलग-अलग लोगों को बेचा गया। जांच दस्तावेजों के अनुसार वर्तमान में इस जमीन पर 17 कब्जाधारी मौजूद हैं और कई हिस्सों में पक्के निर्माण भी कर लिए गए हैं।

बीजेपी विधायक रामकुमार टोप्पो पर एफआईआर

सरगुजा। सीतापुर से बीजेपी विधायक रामकुमार टोप्पो पर अंबिकापुर कोतवाली पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है। बीजेपी विधायक रामकुमार टोप्पो पर सरकारी काम में बाधा डालने और नायब तहसीलदार तुषार मानिक के साथ मारपीट करने का आरोप है। दर्ज अपराध में विधायक के साथ-साथ समर्थकों पर भी मारपीट करने का आरोप है। अंबिकापुर कोतवाली पुलिस ने जीरो पर यह अपराध दर्ज किया है, अब ये केस डायरी सीतापुर थाने को भेजी जाएगी। दरअसल, बुधवार देर शाम नायब तहसीलदार तुषार मानिक ने बीजेपी विधायक और उनके समर्थकों पर मारपीट करने का आरोप लगाया। नायब तहसीलदार ने अपनी शिकायत में कहा कि विधायक समर्थकों ने पहले उनके साथ मारपीट की फिर विधायक जी ने भी उनको पीटा। पीड़ित नायब तहसीलाद तुषार मानिक की शिकायत पर सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया गया है। विधायक पर सरकारी काम में बाधा डालने का भी आरोप लगा है।

सामूहिक कन्या विवाह में बेमेतरा विधायक भी लेंगे सात फेरे

बेमेतरा। जिले के ऐतिहासिक बेसिक स्कूल खेल मैदान में 31 मई को मुख्यमंत्री कन्या विवाह कार्यक्रम होने जा रहा है। खास बात यह है कि इस सामूहिक विवाह में एक विधायक भी शादी कर दंपत्य जीवन की शुरुआत करने जा रहे हैं। सामूहिक विवाह में कुल 24 जोड़े शादी करेंगे। बेमेतरा में होने वाले मुख्यमंत्री कन्या विवाह आयोजन में बेमेतरा के ही विधायक दीपेश साहू परिणय सूत्र में बंधेंगे, जिसे लेकर तैयारियों का सिलसिला जारी है। विवाह समारोह में विस अध्यक्ष रमन सिंह, प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के साथ ही केंद्रीय राज्य मंत्री तीरुन साहू भी शामिल होंगे। बेमेतरा के विधायक दीपेश साहू ने ईटीवी भारत से फोन पर बातचीत की। उन्होंने कहा कि शासकीय योजना तभी सफल होती है जब एक जनप्रतिनिधि स्वयं इसे अपनाकर समाज के सामने अपना उदाहरण प्रस्तुत करे। विधायक की शादी ने इस समारोह को रोचक बना दिया है प्रदेश में यह पहली बार होगा जब किसी विधायक ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत सात फेरे लेने का फैसला लिया हो।

चंदा के चकोर ने जीता नक्सलगढ़ का दिल

नारायणपुर। बस्तर नक्सलमुक्त हो चुका है। नक्सलमुक्त बस्तर की तस्वीर को बदलने की कोशिशें लगातार जारी है। इसी कड़ी में बुधवार को एनएसडी (नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा) के सहयोग के एक नाटक का मंचन एजी सिनेमा हॉल में किया गया जिसका टाइटल था, चंदा के चकोर। इन नाटक के जरिए छत्तीसगढ़ और खासकर बस्तर की समृद्ध संस्कृति को दिखाया गया। नाटक के जरिए ये बताया गया कि बस्तर के लोग कितने प्रकृति प्रेमी और जीवट होते हैं। नाटक की कहानी अबूझझड़ के एक अविक्तसित गांव की पृष्ठभूमि पर आधारित है। जिसमें चंदा और चकोर की प्रेम कथा के माध्यम से गांव से संसद तक विकास और लोकतांत्रिक व्यवस्था का संदेश दिया गया। मंचन में आदिवासी देवी-देवताओं की आस्था, विवाह परंपराएं, मेला-मंडई, लोकगीत, पारंपरिक वेशभूषा और जनजातीय संस्कृति का अत्यंत जीवंत चित्रण किया गया है। कलाकारों ने शिक्षा, सामाजिक परिवर्तन और लोकतंत्र की महत्ता को प्रभावशाली ढंग से मंच पर प्रस्तुत किया गया।

अवैध रेत उत्खनन पर बलरामपुर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई

बलरामपुर। जिले में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन के खिलाफ प्रशासन लगातार सख्त कार्रवाई कर रहा है। कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी के निर्देशन में खनिज विभाग द्वारा जिलेभर में विशेष अभियान चलाकर अवैध गतिविधियों पर निगरानी रखी जा रही है। इसी क्रम में विकासखंड रामचंद्रपुर के ग्राम पंचायत धौली लिबरा स्थित रेत खदान का औचक निरीक्षण किया गया, जहां कन्हर नदी किनारे नियम विरुद्ध रेत उत्खनन में संलिप्त एक चीन माउंटेड मशीन को जब्त किया गया। खनिज अधिकारी श्री राहुल गुलाटी ने बताया कि रामचंद्रपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचावल स्थित पांगन नदी में वर्तमान में तीन रेत खदानें स्वीकृत एवं संचालित हैं। विभिन्न माध्यमों से प्राप्त शिकायतों के आधार पर निरीक्षण के दौरान नदी किनारे पोकेलन मशीन से

नियम विरुद्ध उत्खनन में संलिप्त चीन माउंटेड मशीन जब्त



अवैध उत्खनन किए जाने की पुष्टि हुई, जिसके बाद मशीन को तत्काल जब्त कर नियमानुसार कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि इससे पूर्व भी ग्राम पंचावल क्षेत्र में अवैध खनन एवं परिवहन के मामलों में कार्रवाई की जा चुकी है।

पांगन नदी में अवैध रूप से रैम्य और रास्ता निर्माण करते पाए जाने पर एक जेसीबी वाहन जब्त किया गया था तथा

एक लाख रुपये की शस्तित राशि शासकीय कोष में जमा कराई गई। वहीं अवैध रेत भंडारण के मामले में एक जेसीबी और हाइवा वाहन जब्त कर 42 हजार 850 रुपये की वसूली की गई। खनिज विभाग की टीम ने मई 2026 के दौरान राजपुर, बरियों और शंकरगढ़ क्षेत्र में महान नदी एवं गलफूला नदी से अवैध रेत परिवहन करते हुए 19 वाहनों को भी जब्त किया है। इन

वाहनों को सुरक्षार्थ संबंधित थाना और पुलिस सहायता केंद्रों में रखा गया है। जिले में अवैध खनन, परिवहन और भंडारण के विरुद्ध चल रही कार्रवाई का प्रभाव लगातार दिखाई दे रहा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल 152 प्रकरण दर्ज किए गए, जिनमें से 142 प्रकरणों का निराकरण करते हुए 35 लाख 2 हजार 524 रुपये की वसूली की गई।

वहीं शेष मामलों में नोटिस जारी कर कार्रवाई प्रक्रिया जारी है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में अब तक 12 प्रकरण दर्ज किए जा चुके हैं, जिनमें 1 लाख 78 हजार 880 रुपये की वसूली की गई है।खनिज विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण के खिलाफ अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।

दूरस्थ वनांचल में पहुंची विकास की रोशनी : मंत्री राजवाड़े

सूरजपुर। शासन की संवेदनशील पहल और जनसेवा के प्रति प्रतिबद्धता का एक प्रेरणादायक उदाहरण सूरजपुर जिले के अत्यंत दूरस्थ वनांचल ग्राम बेलामी, पंचायत घुईडीह, 2025-26 में कुल 152 प्रकरण दर्ज किए गए, जिनमें से 142 प्रकरणों का निराकरण करते हुए 35 लाख 2 हजार 524 रुपये की वसूली की गई।

वहीं शेष मामलों में नोटिस जारी कर

कार्रवाई प्रक्रिया जारी है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में अब तक 12 प्रकरण दर्ज किए जा चुके हैं, जिनमें 1 लाख 78 हजार 880 रुपये की वसूली की गई है।खनिज विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण के खिलाफ अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।

ग्रामीणों के चेहरों पर लौटी मुस्कान

ही ग्रामीणों के चेहरे खिल उठे। गांव के लोगों ने इसे केवल तकनीकी सुधार नहीं, बल्कि संवेदनशील जनप्रतिनिधित्व और ग्रामीण हितों के प्रति जिम्मेदारी का प्रतीक बताया।

ऋेडा विभाग के जिला प्रभारी श्री सुजोित श्रीवास्तव की उपस्थिति में सुधार कार्य सम्पन्न हुआ। इस दौरान श्री विजय प्रजापति सहित मोहल्लेवासियों ने मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि दूरस्थ वनांचल क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए उनका लगातार सक्रिय रहना ग्रामीणों में विश्वास और नई उम्मीद जगा रहा है।

संक्षिप्त समाचार

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने वीर सावरकर की जयंती पर किया श्रद्धापूर्वक नमन

रायपुर। वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने मां भारती के अमर सपूत एवं महान क्रांतिकारी ‘स्वातंत्र्यवीर’ विनायक दामोदर सावरकर जी की जयंती पर उन्हें कोटि-कोटि नमन करते हुए श्रद्धापूर्वक स्मरण किया है। वित्त मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि वीर सावरकर जी ने जीवनभर राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रीय चेतना और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। उनकी क्रांतिकारी सोच, प्रखर लेखनी और अटूट साहस ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को वैचारिक शक्ति प्रदान की। उन्होंने कहा कि वीर सावरकर जी का जीवन देशभक्ति, त्याग और समर्पण का अनुपम उदाहरण है। विपरीत परिस्थितियों में भी राश्रहित के प्रति उनकी प्रतिबद्धता हर भारतीय को प्रेरित करती है। वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने कहा कि वीर सावरकर जी के विचार और आदर्श आने वाली पीढ़ियों को राष्ट्रसेवा के लिए सदैव प्रेरित करते रहेंगे।

पंडवानी गायिका तीजन बाई

रायपुर एम्स में दाखिल

दुर्ग। सुप्रसिद्ध पंडवानी लोक गायिका और



पद्मविभूषण से सम्मानित डॉ. तीजन बाई को तबीयत अचानक बिगड़ने के बाद रायपुर एम्स में भर्ती कराया गया है। तीजन बाई को शुरुआत में ट्रॉमा एवं इमरजेंसी विभाग में लाया गया था, जिसके बाद उन्हें मेडिकल इंटेंसिव केयर यूनिट में स्थानांतरित किया गया है। तीजन बाई की बहु वेगु देशमुख ने बताया कि रात करीब 11 बजे उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया। डॉक्टरों द्वारा किए गए संपूर्ण चेकअप और मेडिकल रिपोर्ट्स के बाद यह बात सामने आई है कि उनके फेफड़ों में पानी बढ़ गया है, और उन्हें निमोनिया की भी शिकायत है। इसके अलावा उनका ब्लड प्रेशर भी काफी लो है। हालांकि, बहू ने राहत की खबर साझा करते हुए कहा कि तुरंत एम्बुलेंस से एम्स लाने और त्वरित इलाज मिलने के बाद अब उनकी स्थिति पहले से बेहतर है, और वे खतरे से बाहर हैं। इस बीच तीजन बाई का परिवार और उनके अनगिनत प्रशंसक उनके जल्द स्वस्थ होकर घर लौटने की दुआ कर रहे हैं। फिलहाल, डॉक्टरों की एक विशेष टीम उनकी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है।

पूर्व भारतीय क्रिकेटर व छत्तीसगढ़ क्रिकेट टीम के कोच अमय मिले सीएम साय से



रायपुर। रायपुर स्थित निवास में आज पूर्व भारतीय क्रिकेटर एवं छत्तीसगढ़ क्रिकेट टीम के कोच अमय खुरासिया ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान प्रदेश के

युवा क्रिकेट प्रतिभाओं को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने, खेल अधीसंरचना को सशक्त बनाने और छत्तीसगढ़ में खेल संस्कृति को प्रोत्साहित करने संबंधी विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई।इस अवसर पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता श्री अमित चिमनानी भी उपस्थित थे।

अस्थिबाधित दिव्यांगजनों के लिए 5 जून को रोजगार मेला, 6 कंपनियां देंगी नौकरी

रायपुर। विशेष रोजगार कार्यालय, रायपुर द्वारा अस्थिबाधित दिव्यांगजनों के लिए 5 जून को रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। यह मेला सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक शासकीय कन्या पॉलिटेक्निक कॉलेज, बैरन बाजार, रायपुर में होगा। उपसंचालक डॉ. शशी अतुलकर ने बताया कि यंग इंडिया के तत्वावधान में होने वाले इस रोजगार मेले में 6 कंपनियां शामिल होंगी। क्रेडालिस केपिटल प्रा. लिमिटेड, आई. ट्रेड टेलिमेडिक्स निगरानी जी.पी.एस., रामा उद्योग प्रा. लिमिटेड, बारबरिक ट्रान्सफार्मर्स, अविनाश डेव्लपर्स प्रा. लिमिटेड एवं स्काई ऑटोमोबाईल मारुति नेक्सा, रायपुर द्वारा योग्यता के अनुसार अस्थिबाधित दिव्यांगजनों को रोजगार दिया जाएगा। चयनित युवाओं को योग्यता और पद के अनुसार 11,000 रुपये से 30,000 रुपये तक मासिक वेतन मिलेगा। सभी का कार्यक्षेत्र जिला रायपुर रहेगा। छत्तीसगढ़ के ऐसे अस्थिबाधित दिव्यांगजन जिनकी उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच है और जो बिना व्हीलचेयर के चलने फिरने में सक्षम हैं, वे इस मेले में शामिल हो सकते हैं। आवेदकों को 10वीं, 12वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, आई. ई., आई.टी.आई., डीसीए, पीजीडीसीए आदि की अंत्कमची, तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की मूल प्रतिये एक फोटोकॉपी तथा 2 पासपोर्ट साइज फोटो लेकर आना होगा। आवेदकों को आने जाने का कोई खर्च नहीं दिया जाएगा। खाने पीने और ठहरने की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। अधिक जानकारी के लिए कार्यालयीन समय में फोन नंबर 0771-4044081 पर संपर्क कर सकते हैं।

राजधानी/छत्तीसगढ़

राज्य सरकार की जनहितैषी योजनाओं से कांग्रेस के पेट में हो रहा दर्द : अरुण साव

रायपुर। छत्तीसगढ़ में इन दिनों महतारी वंदन को लेकर सियासत जारी है। छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने प्रदेश में शराब और महतारी वंदन योजना को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के बयानों पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की जनहितैषी योजनाओं से कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है।

सरगुजा में शराब को लेकर महिलाओं के प्रदर्शन पर दीपक बैज के बयान पर अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस की सरकार में घर-घर शराब पहुंचाई गई, पूरे प्रदेश को नशे का अड्डा बना दिया गया और बड़ा शराब घोटाला हुआ। आज जब हमारी सरकार में 70 लाख महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ मिल रहा है और वे आर्थिक रूप से सक्षम हो रही हैं, तो कांग्रेस को परेशानी हो रही है। उन्होंने साफ किया कि 18 लाख परिवारों को पीएम आवास का लाभ मिला है और प्रदेश की जनता अब कांग्रेस के बहकावे में नहीं आने वाली।

डिप्टी सीएम अरुण साव ने सूरजपुर में कांग्रेस नेताओं की एकजुटता पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता कभी आम जनता के मुद्दों पर खड़े नहीं होते, वे हमेशा खामोश रहते हैं। साव ने आरोप लगाया कि कांग्रेसी सिर्फ अपराधियों के लिए ही एकजुट होते हैं। यही वजह है कि प्रदेश की जनता

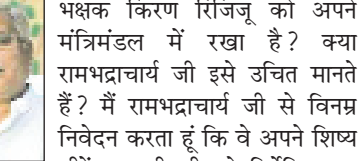


चुकी है। इससे उनका सनातन विरोधी चेहरा बार-बार उजागर होता है। साव ने खुली चुनौती देते हुए कहा, अगर कांग्रेस में हिम्मत है, तो किसी अन्य धर्म के संत के खिलाफ बोलकर दिखाएं। इस तरह की अमर्यादित टिप्पणी बेहद दुर्भाग्यजनक है और इसका अधिकार किसी को नहीं है। एक्सप्रेसवे को ट्रैफिक के लिए खोले जाने के सवाल पर अरुण साव ने कहा कि यह पूरा मामला सरकार के संज्ञान में है और इसकी गहन जांच की जा रही है। जांच रिपोर्ट के आधार पर उचित निर्णय लेकर कार्रवाई की जाएगी। वहीं, सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो और तहसीलदार के बीच हुए विवाद और मारपीट के मामले पर डिप्टी सीएम ने संभलकर बयान देते हुए कहा कि इस मामले की जांच की जा रही है, जांच पूरी होने के बाद ही पूरी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

भूपेश बघेल का रामभद्राचार्य पर निशाना, बोले- फ्यूल सस्ता कराने के लिये अपने चेले धीरेंद्र से निकलवाएं पर्ची

रायपुर। छत्तीसगढ़ में जगतगुरु रामभद्राचार्य और बागेश्वर धाम सरकार पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्रकृष्ण शास्त्री को लेकर जमकर सियासत गरमाई हुई है। छत्तीसगढ़ नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के बाद अब प्रदेश के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भी उन्हें निशाने पर लिया है।

बघेल ने एक बार फिर धार्मिक और राजनीतिक मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने जगद्गुरु रामभद्राचार्य पर तंज कसते हुए कहा कि वे अपने चेले कथावाचक पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री से पेट्रोल-डीजल के दाम कम करवाएं। कटाक्ष करते हुए कहा कि यदि धीरेंद्र शास्त्री पच्ची देखकर सब कुछ बता सकते हैं, तो उन्हें रामभद्राचार्य से निर्देश लेकर देश में पेट्रोल और डीजल के दाम भी कम कराने चाहिए। पूर्व सीएम बघेल ने रामभद्राचार्य और पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पर टवीट कर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि रामभद्राचार्य जी गौ-भक्त हैं, राम भक्त हैं तो वे ये बताएं कि मोदी जी ने तो गौ-मांस



के पेट्रोल-डीजल के दाम कम करवाएं और रामभद्राचार्य जी बड़े ज्ञानी और गुणी हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि ये मोदी जी ट्रंप के सामने इतना झुक क्यों जाते हैं, आप अपनी दिव्यदृष्टि से देख कर बताएं।

उन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पर निशाना साधते हुए कहा कि आरएसएस आज खुद को हिंदू धर्म का सबसे बड़ा ठेकेदार मानने लगा है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब रामभद्राचार्य जैसे संत कहते हैं कि कई संतों को संस्कृत तक का ज्ञान नहीं है, तो फिर यह कैसे तय किया जाता है कि कौन धर्म का प्रतिनिधित्व करेगा। बघेल ने यह भी कहा कि मोहन भागवत ने आज तक सार्वजनिक रूप से संस्कृत का कोई श्लोक नहीं बोला है, फिर भी उन्हें इस भूमिका में क्यों देखा जाता है।

लोक निर्माण विभाग के सचिव ने सड़कों का काम देखा

■ अधिकारियों की बैठक लेकर काम में तेजी लाने दिए निर्देश

रायपुर। लोक निर्माण विभाग के सचिव श्री मुकेश कुमार बंसल ने आज बिलासपुर में नेहरू चौक से दर्राघाट तक बन रहे 10 किमी फोरलेन सड़क के कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने मौके पर मौजूद वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों और ठेकेदार को कार्यों में तेजी लाते हुए इसे जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों की बैठक लेकर बिलासपुर जिले में महत्वपूर्ण सड़कों और भवनों के निर्माण की प्रगति की भी समीक्षा की। लोक निर्माण विभाग के सचिव ने बिलासपुर परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता, कार्यापालन अभियंताओं और अनुविभागीय अधिकारियों से कहा कि हर कार्य के



विभिन्न चरणों के लिए समय-सीमा निर्धारित कर कार्यों में तेजी लाएं। कार्यों की रोज मॉनिटरिंग कर तथा ठेकेदारों से समन्वय बनाकर समय-सीमा में काम पूरा कराएं। उन्होंने निविदा स्वीकृति के एक माह के भीतर हर हाल में काम प्रारंभ कराने के निर्देश दिए। बिलासपुर के कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल, जिला पंचायत के सीईओ श्री संदीप अग्रवाल, लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता श्री वी.के. भतपहरी, मुख्य अभियंता श्री आर.के. रात्रे और अधीक्षण अभियंता

ने इन्हें पूरी तरह नकार दिया है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस जिसके लिए आंदोलन कर रही थी, उसके खिलाफ आर्मस एक्ट जैसी गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज है।

जगद्गुरु रामभद्राचार्य पर कांग्रेस से जुड़े महंत की टिप्पणी पर आक्रोश जताते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि हिंदू देवी-देवताओं और संत-महात्माओं के खिलाफ टिप्पणी करना कांग्रेस की पुरानी आदत बन चुकी है। इससे उनका सनातन विरोधी चेहरा बार-बार उजागर होता है। साव ने खुली चुनौती देते हुए कहा, अगर कांग्रेस में हिम्मत है, तो किसी अन्य धर्म के संत के खिलाफ बोलकर दिखाएं। इस तरह की अमर्यादित टिप्पणी बेहद दुर्भाग्यजनक है और इसका अधिकार किसी को नहीं है। एक्सप्रेसवे को ट्रैफिक के लिए खोले जाने के सवाल पर अरुण साव ने कहा कि यह पूरा मामला सरकार के संज्ञान में है और इसकी गहन जांच की जा रही है। जांच रिपोर्ट के आधार पर उचित निर्णय लेकर कार्रवाई की जाएगी। वहीं, सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो और तहसीलदार के बीच हुए विवाद और मारपीट के मामले पर डिप्टी सीएम ने संभलकर बयान देते हुए कहा कि इस मामले की जांच की जा रही है, जांच पूरी होने के बाद ही पूरी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

कृषि विवि में तीन दिवसीय राष्ट्रीय आम महोत्सव आज से

■ 250 से अधिक किस्मों का किया जाएगा प्रदर्शन

रायपुर। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर तथा संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, छत्तीसगढ़ शासन तथा प्रकृति की ओर सोसायटी के संयुक्त तत्वावधान में दिनांक 29, 30 एवं 31 मई, 2026 को कृषि महाविद्यालय परिसर रायपुर में तीन दिवसीय राष्ट्रीय आम महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। तीन दिवसीय राष्ट्रीय आम महोत्सव का शुभारंभ 29 मई, 2026 को किया जाएगा। राष्ट्रीय आम महोत्सव में आम की 250 से अधिक किस्मों का प्रदर्शन किया जायेगा। इस कार्यक्रम में आम की विभिन्न किस्मों की प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही है जिसमें छत्तीसगढ़ एवं देश के विभिन्न राज्यों के आम उत्पादक शामिल होंगे। इस अवसर पर आम से बने विभिन्न व्यंजनों की प्रतियोगिताएं भी आयोजित हैं। आम की सजावट प्रतियोगिता भी आयोजित की जा रही है जिसमें विद्यालयीन एवं महाविद्यालयीन विद्यार्थी, महिलाएं तथा अन्य सामान्यजन भी पंजीयन कर भागीदारी कर सकते है। इस महोत्सव में पंजीयन एवं प्रवेश पूर्णतया निशुल्क है। राष्ट्रीय आम महोत्सव में संस्थागत एवं व्यक्तिगत प्रतियोगी भी सहभागी हो सकते हैं। आम महोत्सव के दौरान आम पर केंद्रित मँगो क्रिज मँगो, फेंसी ड्रेस आदि प्रतियोगिताएं भी



अयोजित की जाएगी। इसके अलावा प्रतिदिन सांस्कृतिक संंध्या का भी आयोजन किया जाएगा।

राष्ट्रीय आम महोत्सव में 29 से 31 मई, 2026 तक विभिन्न श्रेणियों में प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा जिसमें किसानों द्वारा उत्पादित आम की व्यावसायिक किस्मों के अंतर्गत दशहरी, लंगडा, बान्ने ग्रीन, चैसा, मालदा, हिमसागर, सुन्दरजा, केसर, अलफान्सो, तोतापरी, नीलम, बैंगनफल्ली, पैरी, सिन्दूरी, फजुली आदि किस्मों की प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। संकर किस्मों की प्रतियोगिता के अंतर्गत मल्लिका, आभ्रपाली, पूसा अरुणिमा, अम्बिका, रत्ना, सिंधु, अकां पुनीत किस्मों को शामिल किया गया है। विशिष्ट किस्मों की प्रतियोगिता के अंतर्गत हाथीझुल, नूरजहां, लड्डू, गुलाब खास किस्मों के उत्पादक भाग ले सकते हैं। एकजुटिक (आयातित किस्म) की प्रतियोगिता में मियाजाकी, टॉमी एटकिन्स एवं गोल्डन

मुख्यमंत्री ने स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर की जयंती पर उन्हें किया नमन

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने गुरुवार को यहां अपने निवास कार्यालय में महान क्रांतिकारी, प्रखर राष्ट्रवादी चिंतक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी विनायक दामोदर सावरकर की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धापूर्वक नमन किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि वीर सावरकर केवल स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी ही नहीं बल्कि राष्ट्रचेतना, साहस और सामाजिक जागरण के प्रखर प्रतीक थे। उन्होंने मातृभूमि की स्वतंत्रता और राष्ट्रीय स्वाभिमान के लिए अपना संपूर्ण जीवन संघर्ष और तपस्या में समर्पित किया। कठिन परिस्थितियों और यातनाओं के बावजूद उनका राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत संकल्प कभी डगमगाया नहीं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वीर सावरकर ने समाज में



अवैध निर्माण को संरक्षण देने और निगम के अधिकारियों पर कार्रवाई न करने का दबाव बनाने के भी आरोप हैं। पार्षदों की नाराजगी की सबसे बड़ी वजह बोरियाकला में एक अवैध अस्पताल पर होने वाली निगम की कार्रवाई को रुकवाना बताया जा रहा है। इस मुद्दे पर भाजपा नेताओं और जनप्रतिनिधियों के बीच करीब 2 घंटे तक एक बंद कमरे में बैठक हुई। चूंकि सचिन मेघानी को रायपुर के दिग्गज भाजपा नेता और सांसद बृजमोहन अग्रवाल का बेहद करीबी माना

जाता है, इसलिए इस पूरे मामले ने शहर की सियासत में भारी गरमाहट ला दी है।

महापौर मीनल चौबे ने कहा कि जोन अध्यक्ष को हटाने के संबंध में पार्षदों का एक मांग पत्र मुझे प्राप्त हुआ है। इस पूरे मामले में विचार होगा कि क्या कर सकते हैं।

जोन अध्यक्ष सचिन मेघानी ने सफाई देते हुए कहा कि मेरे खिलाफ किस तरह का पत्राचार हुआ है, फिलहाल मुझे इसकी आधिकारिक जानकारी नहीं है। मैं इस विषय में भाजपा संगठन, जिलाध्यक्ष और महापौर से सीधा संवाद करूंगा। संगठन मुझे से जो भी स्पष्टीकरण या जानकारी मांगेगा, मैं उसे देने के लिए तैयार हूँ। जोन के सभी सातों पार्षद आपस में एक परिवार की तरह हैं। मुझे लगता है कि विरोधी दल हमारे बीच मनमुटाव पैदा करने की कोशिश कर रहा है।

मुख्यमंत्री ने स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर की जयंती पर उन्हें किया नमन



नगोट्स किस्मों को शामिल किया गया है। इस अवसर पर आम से निर्मित उत्पादों की प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा जिसमें प्रतिभागी आम से निर्मित उत्पाद – नेक्टर/आर.टी.एस., शर्बत, पना, आम के अचार, आम की चटनी, आम पापड़, आमरस, जैम एवं मिठाई आदि व्यंजनों के साथ प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय आम महोत्सव में प्रतिभागियों हेतु आम आधारित मॉडल एवं बोनसाई, आम आधारित सजावट प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर प्रकृति की ओर सोसायटी की ओर से आम की ग्यारह गुठलियाँ लाने वाले व्यक्तियों को एक उन्नत किस्म के आम का पौधा दिया जाएगा। प्रसिद्ध शेफ आकांक्षा राॅय आम के व्यंजन बनाना भी सिखाएंगी।

आयोजन के प्रथम दिवस 29 मई को प्रातः 9 बजे से 12 बजे तक प्रविष्टियों का पंजीयन किया जाएगा। इसके पश्चात सामान्यजनों के लिए प्रदर्शनी अवलोकनार्थ तीनों दिन सायं 9 बजे तक खुली रहेगी। प्रदर्शनी में आम की विभिन्न किस्मों के फल, आम के विभिन्न उत्पाद एवं आम के पौधे भी विक्रय के लिए उपलब्ध रहेंगे। द्वितीय दिवस 30 मई को आम उगाने वाले कृषकों एवं जिज्ञासुओं के लिए 12 बजे से 4 बजे तक आम उत्पादन समस्या एवं समाधान विषय पर तकनीकी मार्गदर्शन एवं परिचर्चा का आयोजन किया गया है।

मुख्यमंत्री ने स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर की जयंती पर उन्हें किया नमन



व्यास हुआदूत और भेदभाव जैसी कुरीतियों के खिलाफ भी मुखर होकर आवाज उठाई और सामाजिक समरसता तथा राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने का सतत प्रयास किया। उनकी लेखनी, विचार और काम आज भी

देशवासियों को राष्ट्रहित, आत्मगौरव और सामाजिक सद्भाव की प्रेरणा देते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वीर सावरकर अपने विचारों से आज भी हमारी युवा पीढ़ी को राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करते हैं। हमें उनके आदर्श पथ पर अग्रसर होते हुए एक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए नितर प्रयासरत रहना चाहिए। इस अवसर पर वित्तमंत्री श्री ओपी चौधरी, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के अध्यक्ष श्री नीलू शर्मा भी उपस्थित थे।

विश्रामपुर विवाद पर कांग्रेस पीसीसी चीफ दीपक बैज ने उठाए सवाल

■ कहा- क्या प्रदेश में दो तरह का कानून चल रहा? एफआईआर दर्ज कराने धरने पर बैठना पड़ा

रायपुर। दीपक बैज ने विश्रामपुर मामले को लेकर भाजपा सरकार और पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व संसदीय सचिव विकास उपाध्याय और वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजेंद्र तिवारी भी मौजूद रहे। दीपक बैज ने कहा कि 25, 26 और 27 मई को सूरजपुर जिले के विश्रामपुर थाने के सामने कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया। जनता को यह जानना जरूरी है कि आखिर कांग्रेस को धरने पर क्यों बैठना पड़ा। बैज ने आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर शिवदंदनपुर नगर पंचायत का चुनाव रोककर रही थी, क्योंकि यह क्षेत्र कांग्रेस का गढ़ रहा है। नगर पंचायत उपचुनाव में भाजपा बैकफुट पर है और इसी वजह से राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा है।

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बैज ने आरोप लगाया कि पार्टी के जिला उपाध्यक्ष और उनकी पत्नी के साथ भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने घर पहुंचकर दुर्व्यवहार किया। साथ ही भाजपा जिलाध्यक्ष के कहने पर कांग्रेस के ही उपाध्यक्ष के खिलाफ आर्मस एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर दी गई। पुलिस के पास इस



मामले में कोई ठोस सबूत नहीं है और पूरी कार्रवाई एकरफा की गई। जब कांग्रेस ने इसका विरोध किया तो पहले दिन कोई अधिकारी चर्चा करने नहीं आया, दूसरे दिन भी प्रशासन की ओर से कोई पहल नहीं हुई। इसके बाद कांग्रेस नेताओं ने आमरण अनशन शुरू किया। दीपक बैज ने बताया कि धरना और अनशन के दबाव के बाद रात करीब 12 बजे भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा, क्या प्रदेश में दो तरह का कानून चल रहा है? एफआईआर करवाने के लिए हमें धरने पर बैठना पड़ा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष नरेंद्र जैन को लगातार डराया और धमकाया जा रहा है।

दीपक बैज ने अपने मोबाइल चोरी मामले को लेकर

प्रदेश सरकार और पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े किए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैज ने कहा कि अब तक उनका चोरी हुआ मोबाइल बरामद नहीं किया जा सका है, जबकि अन्य मामलों में पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की। बैज ने कहा कि पूर्व नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक का मोबाइल मिल गया, वहीं भाजपा विधायक पुरंदर मिश्रा से ठगी करने वाले आरोपी को भी मोबाइल ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उनका पुलिस अब तक नहीं मिला। उन्होंने तंज

कसते हुए कहा, दीपक बैज का मोबाइल चूम गया, लेकिन पकड़ाया नहीं। वो चाहते हैं कि विपक्ष का सब कुछ चूम जाए। बैज ने आरोप लगाया कि प्रदेश की सरकार केवल भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए काम कर रही है, जबकि आम जनता और विपक्ष की समस्याओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए सरकार है, आम जनता के लिए नहीं। दीपक बैज ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैज ने कहा कि छत्तीसगढ़ में आम जनता खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है। अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लूट, चोरी, गोलीबारी, चाकूबाजी और जानलेवा हमले जैसी घटनाएं खुलेआम हो रही हैं। जनता सड़क पर उतकर सरकार के खिलाफ

प्रदर्शन कर रही है, लेकिन सरकार हालात संभालने में विफल साबित हो रही है। बैज ने कहा, हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं तो हमें कहा जा रहा है कि हम गुंडागर्दी कर रहे हैं।

बैज ने भाजपा विधायक रामकुमार टोप्पो पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि विधायक टोप्पो ने तहसीलदार को कमरे में बंद कर मारपीट की, लेकिन सरकार इस मामले में कार्रवाई करने से बच रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री से सवाल करते हुए कहा, मुख्यमंत्री को बताया चाहिए कि वे अपने विधायक के खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार विपक्ष की आवाज दबाने का काम कर रही है, जबकि सत्ता पक्ष के नेताओं पर लगे गंभीर आरोपों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है।

दीपक बैज ने भाजपा विधायक दीपेश साहू के मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शादी करने के फैसले पर सवाल उठाए हैं। बैज ने कहा कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए बनाई गई है। क्या भाजपा विधायक दीपेश साहू गरीबी रेखा में आते हैं? बैज ने इसे भाजपा का पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा करार देते हुए कहा कि इस तरह के कदम केवल राजनीतिक संदेश देने के लिए उठाए जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने विधायक दीपेश साहू को शादी की शुभकामनाएं भी दीं।

कर्नाटक से कांग्रेस का सशक्त संदेश

दिलीप कुमार पाठक

कांग्रेस पार्टी आजकल जिस तरह धड़धड़ और कड़े फैसले ले रही है, उसकी जरूरत उसे बहुत पहले से थी। राजनीति का एक सीधा नियम है – जो नेता वक्त की चाल को नहीं समझ पाता, वो धीरे-धीरे पीछे छूट जाता है। हाल के दिनों में कांग्रेस आलाकमान ने जो फैसले लिए हैं, उसने यह साफ कर दिया है कि अब पार्टी में कोई भी नेता संगठन से बड़ा नहीं है। यह बदलाव कांग्रेस के उन आम कार्यकर्ताओं के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, जो जमीन पर रहकर दिन-रात मेहनत करते हैं। एक पुराना दौर था जब कांग्रेस में फैसले लेने में बहुत देर लगाई जाती थी। बड़े नेताओं की जिद के आगे आलाकमान को झुकना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। राजस्थान का उदाहरण सबके सामने है, पार्टी कभी अशोक गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसा सबसे बड़ा और सम्मानजनक पद देना चाहती थी। लेकिन उस समय उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने का मन नहीं था। उन्होंने वक्त की मांग को नहीं समझा। नतीजा यह हुआ कि समय बदला और आज उन्हें संगठन में एक महासचिव बनने के लिए भी कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। राजनीति का यही दस्तरू है – जो समय की कद्र नहीं करता, समय उसकी कद्र नहीं करता। अशोक गहलोत और कमलनाथ जैसे पुराने नेताओं के लिए यह संभल जाने का आखिरी मौका है। इन बड़े नेताओं को अब यह बात समझ लेनी चाहिए कि अपनी जिद छोड़कर नई पीढ़ी को आगे बढ़ाना ही असली समझदारी है। दूसरी तरफ, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने पूरे देश के नेताओं के सामने एक बहुत सुंदर मिसाल पेश की है, उन्होंने उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार को को गले लगा कर आशीर्वाद दिया और थाना बना दिया कि अगले मुख्यमंत्री होंगे, ये होता है पार्टी के लिए अनुशासन आज वे सिर्फ अपने राज्य के नहीं, बल्कि पूरे देश के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के चहेते नेता बन गए हैं। जब भी पार्टी पर कोई मुश्किल आई या आलाकमान ने कोई कड़ा फैसला सुनाया, सिद्धरमैया ने हमेशा पार्टी की बात को ऊपर रखा। उन्होंने अपनी निजी इच्छाओं को किनारे रखकर संगठन को मजबूत करने का काम किया। यही वजह है कि आज पूरी पार्टी में उनका मान-सम्मान बहुत बढ़ गया है। उत्तर भारत के कांग्रेस नेताओं को इस बात से बहुत कुछ सीखना चाहिए। सच कहें तो दक्षिण भारत की राजनीति ने उत्तर के नेताओं को हमेशा एक नया आईना दिखाया है। इतिहास गवाह है कि जब भी कांग्रेस पार्टी पर कोई बड़ा संकट आया है, दक्षिण भारत ने हमेशा उसे सहारा दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जमाने से लेकर आज के दौर तक, दक्षिण के नेताओं ने पार्टी को मुश्किल दिनों से निकाला है। आज मल्लिकार्जुन खड़गे और सिद्धरमैया जैसे नेता जिस तरह सूझबूझ से काम कर रहे हैं, वह उत्तर भारत के गले-बड़े क्षयों के लिए एक बड़ा सबक है। कांग्रेस का यह नया रूप बता रहा है कि अब सिर्फ पुरानी साख या बड़े नाम के भरोसे मलाईदार पद मिलने के दिन चले गए हैं। अब पार्टी में उसी को तबज्जो मिलेगी जो जमीन पर पसीना बहाएगा और अनुशासन में रहेगा। यह बदलाव पार्टी के उन लाखों कार्यकर्ताओं में नई जान फूंक रहा है जो सालों से बिना किसी स्वा्थ के झंडा उठा रहे हैं। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की जोड़ी ने यह साफ संदेश दे दिया है कि अब कड़े फैसले लेने में कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। इस बदलते हुए दौर की कांग्रेस में अब भावुकता की जगह काम को देखा जा रहा है। पुरानी वफादारी का सम्मान जरूर है, लेकिन पार्टी को कमजोर करने की छूट अब किसी को नहीं मिलेगी। समय रहते अगर पुराने और वरिष्ठ नेता इस सच्चाई को स्वीकार कर लें, तो इसी में उनका सम्मान बचा रहेगा और इसी में कांग्रेस पार्टी का फायदा भी है।

पुराण दिग्दर्शन

सन्देहभासनिकारणाध्यायः (नौवां अध्याय)

(गतांक से आगे...)

कदाचित् शङ्खावादी सज्जनों को इतने पर भी संतोष न तो हो उन्हें कुक्षेत्र जिला करनाल (पंजाब) के किसी बड़े किसान के पास जाकर अपनी तस्बीर करनी चाहिए। क्योंकि इस इलाके में भैंस के तूजाने या फिर जाने पर अर्थात् गर्भश्राव हो जाने की हालत में जमींदार लोग भैंस का बंधा तोड़ने के लिये उसके भैंसे से संयुक्त हो जाने के बाद योनि में हाथ डाल कर अन्दर से सबका सब वीर्य चुसू भर भर कर निकाल लेते हैं और उसे सरसों के तेल भरे बर्तन में रख छोड़ते हैं। पश्चात् उसकी नाक में वह सब का सब वीर्य डाल कर शूथड़ी को खास तरह से घुमाते हैं जिससे वह वीर्य पुनः गर्भाशय में पहुँच जाता है, और भैंस समय पर व्याती है। उनका यह सतत अनुभूत अनुभव है कि यदि भैंस की नासिका के बाएँ छिद्र में

क्रमशः ...

वीर्य डाला जायगा तो अवश्य कटड़ी पैदा होगी, इसी तरह दाईं नाक में डालने पर कटड़ा पैदा होगा। नाक में वीर्य डालते समय यदि भैंस के सामने सफेद चदर तान दी जाए तो उससे भूरी कटड़ी पैदा होने की सम्भावना की जाती है। यह सब क्रिया हमने भी कई बार अपनी आँखों देखी है, यदि अन्य किसी को देखनी हो तो वह भी जब चाहे देख सकता है।

अब विचार करना चाहिये कि जब इस गए गुजरे जमाने में भी भारत के ब्रपचित किसान योनिमार्ग से सेचन किये हुवे पशु वीर्यगत कीटाणुओं को तेल के पात्र में सुरक्षित रखकर पुनः नाक छिद्र द्वारा गर्भाशय में पहुँचा देने की योग्यता रखते हैं, तब हमारे पूर्वज त्रिकालज्ञ महर्षि अमोघ वीर्य के कीटाणुवों को परिपुष्ट करके, सर्वाङ्गपूर्ण मनुष्य बना सकने की योग्यता नहीं रखते थे- इसप्रकार का काम कदा कदा मनहूस खयाल भी करना हम तो कोरी मूर्खता समझेंतें है।

क्रमशः ...



ट्रंप समझ गया कि चीन का मुकाबला अकेले नहीं कर सकता

नीरज कुमार दुवे

अमेरिका को अब इस बात का भलीभाँति एहसास हो चुका है कि चीन जैसी उपरती महाशक्ति को रोक पाना उसके अकेले बूते की बात नहीं रह गई है। यही कारण है कि चीन से लगभग खाली हाथ लौटे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अब उम्मीद की सबसे मजबूत किरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दरबार में दिखाई दे रही है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का भारत दौरा दरअसल इसी बदली हुई वैश्विक मजबूरी और रणनीति का संकेत है। ट्रंप ने जिस तरह भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर से बातचीत के दौरान सार्वजनिक तौर पर कहा कि मुझे प्रधानमंत्री मोदी बहुत पसंद हैं। मोदी महान हैं और वो मेरे दोस्त हैं। ट्रंप ने यह तक कहा कि हम भारत के इतने करीब पहले कभी नहीं थे और भारत मुझ पर तथा अमेरिका पर सी फीसदी भरोसा कर सकता है। यह बयान सिर्फ दोस्ती का प्रदर्शन नहीं, बल्कि उस बदले हुए अमेरिकी रुख का संकेत है जिसमें वॉशिंगटन अब भारत को एशिया में शक्ति संतुलन बनाए रखने वाले सबसे अहम स्तंभ के रूप में देख रहा है। दिलचस्प बात यह भी रही कि मार्को रूबियो ने अपने भारत दौरे में ताजमहल के दीदार का कार्यक्रम भी रखा। कूटनीतिक गलियारों में इसे केवल पर्यटन नहीं, बल्कि एक प्रतीकात्मक संदेश माना जा रहा है, मानो अमेरिका भारत को यह भरोसा दिलाना चाहता हो कि वह इस बार दबाव नहीं, बल्कि मोहब्बत और साझेदारी का पैगाम लेकर आया है।

देखा जाये तो पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका की विदेश नीति में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिले हैं। ट्रंप प्रशासन के दौरान अमेरिका फर्स्ट की नीति ने सहयोगी देशों में असहजता पैदा की। कई देशों को लगा कि वॉशिंगटन अब भरपूर कर नहीं रहा। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। चीन की आर्थिक और सैन्य ताकत जिस तेजी से बढ़ी है, उसने अमेरिका को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि एशिया में उसका प्रभाव बनाए रखने के लिए भारत



जैसी लोकतांत्रिक और उपरती शक्ति के साथ मजबूत रिश्ते जरूरी हैं।

दरअसल, चीन केवल व्यापारिक प्रतिस्पर्धी नहीं रहा। वह अब वैश्विक स्पलाई चैन, तकनीक, रक्षा उत्पादन और सामरिक निवेश के जरिए दुनिया पर अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। दक्षिण चीन सागर से लेकर ताइवान तक, बीजिंग का आक्रामक रवैया अमेरिका के लिए चुनौती बन चुका है। ऐसे में भारत अमेरिका के लिए एक स्वाभाविक विकल्प बनकर उभरा है। भारत एक ऐसा देश है जिसकी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, जिसके पास विशाल बाजार है और जो लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करता है।

अमेरिका यह भी समझ चुका है कि केवल सैन्य शक्ति से चीन को रोकना नहीं जा सकता। इसके लिए आर्थिक नेटवर्क, तकनीकी साझेदारी और भरोसेमंद औद्योगिक ढांचा जरूरी है। यही कारण है कि सेमीकंडक्टर, रक्षा निर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्रिटिकल मिनरल्स और डिजिटल टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में भारत के साथ साझेदारी बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है।

उभर, भारत के लिए भी यह अवसर कम महत्वपूर्ण नहीं है। लंबे समय तक भारत ने गुटनिर्पेक्ष नीति और रणनीतिक स्वायत्तता को प्राथमिकता दी। लेकिन अब नई दिखी समझ रही है कि वैश्विक शक्ति संतुलन में सक्रिय भूमिका निभाए बिना अपने हित सुरक्षित नहीं रखे जा सकते। यही वजह है कि भारत क्राॅड जैसे मंचों में सक्रिय है और अमेरिका, जापान तथा ऑस्ट्रेलिया के साथ सहयोग बढ़ा रहा है। हालाँकि, भारत की चुनौती यह है कि

ज्ञान/मीमांसा

क्या आम आदमी विकास से बाहर छूट रहा है?

ललित गर्ग

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद नए भारत के निर्माण के जिन आधार स्तंभों की कल्पना की गई थी, उनमें शिक्षा और चिकित्सा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। यह माना गया था कि यदि देश के नागरिक शिक्षित, स्वस्थ और जागरूक होंगे तो लोकतंत्र मजबूत होगा, सामाजिक असमानताएं कम होंगी और राष्ट्र विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। शिक्षा को व्यक्ति निर्माण और चिकित्सा को जीवन रक्षा का माध्यम माना गया था। लेकिन स्वतंत्रता के लगभग आठ दशकों बाद स्थिति चिंताजनक प्रश्न खड़े करती है कि क्या ये दोनों क्षेत्र अपने मूल उद्देश्य से भटककर व्यवसाय और बाजार के अधीन नहीं हो गए हैं? आज शिक्षा और चिकित्सा दोनों क्षेत्रों में जो विसंगतियां दिखाई देती हैं, वे केवल व्यवस्थागत संकट नहीं बल्कि सामाजिक संकट का रूप ले चुकी हैं। एक ओर शिक्षा व्यवस्था परीक्षा, अंकों और प्रतिस्पर्धा की आर्थिक मशीन बन गई है, वहीं दूसरी ओर चिकित्सा सेवा लाभ-हानि के गणित में उलझती दिखाई देती है। इन दोनों क्षेत्रों की बढ़ती व्यावसायिकता ने आम आदमी को सबसे अधिक प्रभावित किया है। शिक्षा अब डिग्री, नौकरी और प्रतिस्पर्धा तक सीमित होती दिखाई देती है।

शिक्षा व्यवस्था की विफलताओं का सबसे भयावह चेहरा कोटा, सीकर और अन्य कोचिंग एवं शिक्षा केंद्रों में बढ़ती छात्र आत्महत्याओं के रूप में सामने आया है। कोटा, जो कभी देश की शैक्षणिक आकांक्षाओं का केंद्र माना जाता था, अब विद्यार्थियों पर बढ़ते मानसिक दबाव, प्रतिस्पर्धा, अकेलेपन और असफलता के भय के कारण आत्महत्या की घटनाओं से लगातार चर्चा में रहा है। कोटा, सीकर तथा अन्य कोचिंग नगरों में पिछले वर्षों में अनेक विद्यार्थियों द्वारा आत्महत्या किए जाने की घटनाओं ने शिक्षा व्यवस्था की संवेदनहीनता को उजागर किया है। राजस्थान के सीकर में नीट परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र की आत्महत्या की घटना इसी विडंबना का उदाहरण है। परीक्षा रद्द होने से उत्पन्न अनिश्चितता और मानसिक तनाव ने एक संभावनाशील जीवन समाप्त कर दिया। यह घटना अकेली नहीं है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार वर्ष 2024 में 14,488 विद्यार्थियों ने आत्महत्या की। औसतन हर 36 मिनट में एक विद्यार्थी जीवन समाप्त कर रहा है। यह केवल



व्यक्तिगत विफलता नहीं बल्कि शिक्षा व्यवस्था की सामूहिक विफलता है।

दूसरी ओर नीट, नेट, प्रतियोगी भर्ती परीक्षाओं तथा अन्य राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में बार-बार पेपर लीक, परीक्षा रद्द होने, परिणामों में विवाद और अनिश्चितता की स्थितियों ने विद्यार्थियों में गहरा असंतोष और अविश्वास पैदा किया है। वर्षों की तैयारी करने वाले छात्र जब परीक्षा प्रणाली को ही अविश्वसनीय पाते हैं तो उनमें निराशा और मानसिक तनाव बढ़ता स्वाभाविक है। आज परीक्षा प्रणाली अविश्वसनीय होती जा रही है। प्रश्नपत्र लीक होना, परीक्षाओं का रद्द होना, मूल्यांकन विवाद, शोध कार्यों में साहित्यिक चोरी, पीएचडी प्रक्रियाओं का औपचारिक बन जाना और कोचिंग संस्कृति का बढ़ना शिक्षा के बाजारीकरण की तस्वीर प्रस्तुत करता है। शिक्षा अब ज्ञान से अधिक निवेश और प्रतिफल का विषय बनती जा रही है। धीरे-धीरे शिक्षा सेवा से व्यवसाय में बदलती गई। बड़े निजी विद्यालय, कोचिंग संस्थान और विश्वविद्यालय आज करोड़ों के उद्योग बन चुके हैं। डॉक्टर और इंजीनियर बनाने के सपनों का ऐसा व्यापार खड़ा हुआ जिसमें अधिभावक आर्थिक रूप से टूटने लगे। आज एक सामान्य परिवार अपने बच्चों की शिक्षा के लिए जीवन भर की बचत खर्च करने को विवश है। विद्यालयों की ऊंची फीस, निजी कोचिंग, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और उच्च शिक्षा की महंगी व्यवस्था ने शिक्षा को आम आदमी की पहुंच से दूर कर दिया है।

इसी प्रकार चिकित्सा क्षेत्र की स्थिति भी कम चिंताजनक नहीं है। चिकित्सा को कभी सेवा का क्षेत्र माना जाता था, लेकिन आज निजी चिकित्सालयों की बढ़ती संख्या और उनकी व्यावसायिक प्रवृत्ति ने आम नागरिक को संकट में डाल दिया है। इलाज इतना महंगा हो गया है कि अनेक परिवार बीमारी के कारण आर्थिक रूप से व्सनों में डूब गया। अवसर का लाभ उठाकर हैहय, तालजंघ और शक जातियों ने राज्य पर आक्रमण कर दिया। साथ में यवन, पारद, कांबोज, पह्लव और खस भी हैहयों की सहायता के लिए आ गए। राजा बाहु, अपनी सेना और राज्य, दोनों खो बैठा। वह अपनी गर्भवती पत्नी के साथ वन में चला गया। दुर्भाग्य से उसकी सौत ने उसे विष दे दिया था। फिर भी उसके गर्भ में पल रहे बालक की मृत्यु नहीं हुई। इस बीच वन में राजा बाहु ने प्राण त्याग दिए। उसकी गर्भवती पत्नी बाहु के साथ सती होना चाहती थी। भृगुवंशी महर्षि और्व आ गए। उन्होंने बाहु की पत्नी को बताया कि उसके गर्भ में शिशु जीवित है। कुछ समय बाद बाहु की पत्नी ने एक बालक को जन्म दिया, जो 'रार' (विष) सहित पैदा हुआ था। अतः उसका नाम पड़ा-

टूट जाते हैं। निजी अस्पतालों में उपचार, जांच, आईसीयू, दवाओं का खर्च और नकली दवाओं में जीवन समाप्त होने की घटनाएं लगातार बढ़ी है। अनेक मामलों में अनावश्यक परीक्षण, अत्यधिक शुल्क और व्यावसायिक दृष्टिकोण की शिकायतें सामने आती रहती हैं। चिकित्सा सेवा का उद्देश्य रोगी को राहत देना था, लेकिन कई स्थानों पर वह लाभ कमाने की प्रणाली में बदलती दिखाई देती है। जगह-जगह खुले

निजी अस्पताल और शिक्षण संस्थान एक प्रकार की प्रतिस्पर्धा में उतर आए हैं। लेकिन यह प्रतिस्पर्धा गुणवत्ता की अपेक्षा लाभ कमाने की अधिक दिखाई देती है। परिणाम यह हुआ कि शिक्षा और चिकित्सा दोनों ही सामान्य नागरिक की आर्थिक क्षमता से बाहर जाने लगी हैं। इन परिस्थितियों का एक सामाजिक दुष्परिणाम भी सामने आया है। आर्थिक दबाव, भविष्य की अनिश्चितता, शिक्षा का तनाव, महंगी चिकित्सा और रोजगार संकट के कारण अवसाद, मानसिक तनाव और आत्महत्या की घटनाएं बढ़ रही हैं। युवा पीढ़ी उपलब्धियों के दबाव में टूट रही है, जबकि परिवार आर्थिक बोझ से जूझ रहे हैं।

शिक्षा मंत्रालय को अधिक सशक्त, उत्तरदायी और कठोर भूमिका निभाते हुए परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी, तकनीक आधारित और सुरक्षित बनाना होगा। इसी प्रकार चिकित्सा क्षेत्र में देशभर में स्थापित हुए नए एम्स संस्थानों एवं उच्च चिकित्सा केंद्रों का लाभ वास्तव में आम नागरिक तक सरल, सस्ती और सुलभ व्यवस्था के रूप में पहुंचे, यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है। आज आवश्यकता केवल बड़े अस्पताल बनाने की नहीं, बल्कि उन्हें सर्वसुविधायुक्त, विशेषज्ञ सेवाओं से युक्त तथा दूरराज और पिछड़े क्षेत्रों तक विस्तारित करने की है, ताकि महानगरों पर निर्भरता कम हो और ग्रामीण तथा वंचित वर्ग भी उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं का लाभ सहजता से प्राप्त कर सके। नई शिक्षा नीति के माध्यम से शिक्षा को अधिक व्यावहारिक, कौशल आधारित और बहुआयामी बनाने का प्रयास हुआ है। देश में नए आईआईटी, आईआईएम, केंद्रीय विश्वविद्यालय, एम्स और चिकित्सा संस्थानों की स्थापना की गई। उच्च शिक्षा और उच्च चिकित्सा के नए केंद्र विकसित हुए हैं। मैडिकल कॉलेजों की संख्या में वृद्धि हुई और स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के प्रयास

किए गए।

यह कहना भी उचित नहीं होगा कि पूरा परिदृश्य केवल निराशाजनक है। पिछले वर्षों में शिक्षा और चिकित्सा क्षेत्र में कुछ सकारात्मक प्रयास भी हुए हैं। विशेष रूप से जब से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार आई, तब इन क्षेत्रों की संरचनात्मक कमियों की ओर अपेक्षाकृत गंभीर ध्यान दिया गया। चिकित्सा क्षेत्र में आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं ने गरीब वर्ग को राहत देने का प्रयास किया है। जिला स्तर तक चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार की दिशा में भी पहल हुई है। शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल शिक्षा, कौशल विकास और स्थानीय भाषाओं में अध्ययन पर बल दिया गया। लेकिन भारत जैसी विशाल जनसंख्या वाले देश में ये प्रयास अभी पर्याप्त नहीं कहे जा सकते। जिस गति से जनसंख्या बढ़ी है, उस अनुपात में सरकारी शिक्षा और चिकित्सा संस्थानों का विस्तार नहीं हो पाया। यही कारण है कि निजी क्षेत्र ने उस खाली स्थान को भर दिया और धीरे-धीरे प्रमुख भूमिका में आ गया। अब आवश्यकता केवल नए संस्थान खोलने की नहीं बल्कि सरकारी शिक्षा और चिकित्सा को अधिक प्रभावी, सुलभ और उद्देश्यपूर्ण बनाने की है। सरकारी विद्यालयों और अस्पतालों की गुणवत्ता बढ़ानी होगी। उनमें आधुनिक संसाधन, प्रशिक्षित मानवबल और जवाबदेही सुनिश्चित करनी होगी। निजी शिक्षा और चिकित्सा संस्थानों पर प्रभावी नियंत्रण भी आवश्यक है। शिक्षा और चिकित्सा को पूर्णतः बाजार की शक्तियों पर नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि ये केवल आर्थिक गतिविधियां नहीं बल्कि सामाजिक उत्तरदायित्व हैं। शिक्षा नीति को समाज और जीवन से जोड़ना होगा।

आज आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षा और चिकित्सा को पुनः सेवा और राष्ट्र निर्माण के मूल उद्देश्य से जोड़ा जाए। यदि ये दोनों क्षेत्र केवल व्यापार बन गए तो सामाजिक असमानता और बढ़ेगी, प्रतिभाएं टूटेंगी और आम आदमी विकास की मुख्यधारा से बाहर होता जाएगा। भारत के भविष्य की दिशा इस बात से तय होगी कि शिक्षा और चिकित्सा कितनी सुलभ, समान और मानवीय बनती हैं। सरकार, समाज, नीति निर्माताओं और निजी क्षेत्र को मिलकर ऐसी व्यवस्था विकसित करनी होगी जिसमें कोई बच्चा आर्थिक कारणों से शिक्षा से वंचित न हो और कोई नागरिक उपचार के अभाव में पीड़ित न रहे।

समुद्र का नाम ‘सागर’ कैसे पड़ा?

व्यसनों में डूब गया। अवसर का लाभ उठाकर हैहय, तालजंघ और शक जातियों ने राज्य पर आक्रमण कर दिया। साथ में यवन, पारद, कांबोज, पह्लव और खस भी हैहयों की सहायता के लिए आ गए। राजा बाहु, अपनी सेना और राज्य, दोनों खो बैठा। वह अपनी गर्भवती पत्नी के साथ वन में चला गया। दुर्भाग्य से उसकी सौत ने उसे विष दे दिया था। फिर भी उसके गर्भ में पल रहे बालक की मृत्यु नहीं हुई। इस बीच वन में राजा बाहु ने प्राण त्याग दिए। उसकी गर्भवती पत्नी बाहु के साथ सती होना चाहती थी। भृगुवंशी महर्षि और्व आ गए। उन्होंने बाहु की पत्नी को बताया कि उसके गर्भ में शिशु जीवित है। कुछ समय बाद बाहु की पत्नी ने एक बालक को जन्म दिया, जो 'रार' (विष) सहित पैदा हुआ था। अतः उसका नाम पड़ा-



सगर। सगर युवा हुए, तब उन्हें अपने पिता बाहु के राज्य के हरण का पता चला। फिर उन्होंने पिता का प्रतिशोध लेने के लिए सेना सहित हैहयों पर आक्रमण किया और उन्हें परास्त कर दिया। इसके बाद सगर ने शक, यवन, कांबोज आदि को भी नष्ट करने का निश्चय किया। भयभीत होकर वे सब महर्षि वशिष्ठ की शरण में गए। गुरु वशिष्ठ को आज्ञा मानकर सगर ने उनका वध नहीं किया, पर उनका धर्म और स्वरूप बदल दिया। उन्होंने शकों के आधे सिर मुंडवा दिए, यवनों के पूरे सिर मुंडवा दिए और पह्लवों की दाढ़ियां बढ़वा दीं। पारदों को खुले बाल रखने का आदेश दिया गया। साथ ही, इन सबको वेदाध्ययन और वैदिक कर्मों से वंचित कर दिया गया। इसके बाद राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया। उन्होंने अनेक देशों के

राजाओं को हराकर यज्ञ का घोड़ा छोड़ा। परंतु किसी अज्ञात शक्ति ने उस घोड़े को चुरा लिया और समुद्र के नीचे कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। अश्व के गायब होने से परेशान होकर सगर ने अपने साठ हजार पुत्रों को अश्व खोजने का आदेश दिया। सगर के पुत्र पृथ्वी को खोदते हुए समुद्र तक पहुंच गए। वहां उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। कपिलमुनि समाधि में लीन बैठे थे और पास ही यज्ञ का घोड़ा बंधा था। सगर के पुत्रों ने कपिलमुनि पर चोरी का आरोप लगा दिया। मुनि की समाधि भंग हुई, सगर के पुत्रों की ओर देखा। उनके तेज से सगर के साठ हजार पुत्रों में से चार पुत्र- बह्मकेतु, सुकेतु, धर्मरथ और पंचजन को छोड़कर शेष जलकर भस्म हो गए। तब कपिलमुनि ने वरदान दिया कि इश्वाकुवंश देश अक्षय रहेगा। यह समुद्र उनके नाम से ‘सागर’ कहलाएगा।

आज का इतिहास

- 1914 आयरलैंड के महासागर लाइनर आरएमएस महारानी सेंट लॉरेंस नदी में स्टॉरस्टाड से टकराकर डूब गए, जिसमें 1,012 जहाज पर सवार हुए।
- 1915 तोफिलोब्रागा पुर्तगाल के राष्ट्रपति बने।
- 1935 सबसे अधिक उत्पादित लड़ाकू विमान इन्डिस्टोर के मेसर्सिचट बीएफ 109 की पहली उड़ान थी।
- 1942 बिंग क्रॉस्बी ने व्हाइट क्रिसमस गीत के अपने संस्करण को रिकॉर्ड किया, जो कि अब तक का सबसे अधिक बिकने वाला एकल बन गया, जिसकी 50 मिलियन से अधिक प्रतियां बिकीं।
- 1947 फ्लुग्लैंग द्वीपसमूह पर एक हवाई जहाज पहाड़ी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 25 लोग मारे गए।
- 1948 संयुक्त राष्ट्र सूच पर्यवेक्षण संगठन मध्य पूर्व में शांति स्थापना के लिए स्थापित एक संगठन है। इसका प्राथमिक कार्य मध्य-पूर्व में शांति बनाए रखने वाली ताकतों को सैन्य कमांड संरचना प्रदान कर रहा था, ताकि शांति बनाए रखने वालों को संशर्ष विराम का पालन करने और बनाए रखने में सक्षम बनाया जा सके।
- 1953 एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नॉर्गे माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने।
- 1954 यूरोपीय देशों और संयुक्त राज्य अमेरिका के नेताओं की पहली वार्षिक बिलडरबार्र समूह की बैठक नीदरलैंड्स के ओस्टरबोोक में हुई।
- 1959 चार्ल्स डे गाल फ्रांस के राष्ट्रपति बने।
- 1970 यूनाइटेड रूस ने अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट किया।
- 1972 अभिनेता और पृथ्वी थियेटर के संस्थापक पृथ्वीराज कपूर का निधन हुआ।
- 1982 फॉकलैंड्स युद्ध लगभग 1,000 अर्जेंटीना सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया, जो कि गूज ग्रीन की लड़ाई को समाप्त करता है।
- 1983 नील बोनेट ने चार्लोट मोटर स्पीडवे पर दुनिया के 24 वें दौड़ में अपनी जीत दर्ज कराई।
- 1985 यूरोपियन कप फाइनल से पहले लिवरपूल और जुवेंटस के बीच दंगे से बचने के लिए ब्रसेल्स के हेसेल स्टेडियम की एक दीवार प्रेशर फुटबॉल प्रशंसकों के नीचे गिर गई, जिसमें 39 लोग मारे गए और 600 से अधिक लोग घायल हो गए।
- 1990 दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में आए भीषण भूकंप से 56 मरे।
- 1990 यूरोपीय बैंक पुनर्निर्माण और विकास (ईबीआरडी) की स्थापना।

अमित शाह?, बंगाल के बाद अब मिशन पंजाब!

हरीश गुप्ता

पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक जीत हासिल करने के बाद, जिसे लंबे समय से भाजपा के सबसे कठिन राजनीतिक क्षेत्रों में से एक माना जाता रहा है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अब पंजाब पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। भाजपा के भीतर यह चर्चा जोरों पर है कि शाह अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले सीमावर्ती राज्य में पार्टी के चुनाव प्रचार और संगठनात्मक रणनीति की व्यक्तिगत रूप से देखरेख कर सकते हैं। हालांकि पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी औपचारिक रूप से सुनील बंसल को सौंपी गई थी,

लेकिन पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का मानना ​​है कि चुनाव प्रचार में अमित शाह ने ही केंद्रीय भूमिका निभाई। खबरों के मुताबिक, शाह ने चुनाव के दौरान लगभग दो सप्ताह तक राज्य में डेरा डाला और बुथ स्तर के प्रबंधन व राजनीतिक संपर्क पर बारीकी से नजर रखी। भाजपा नेतृत्व अब पंजाब में भी इसी तरह का जोरदार अभियान चलाने को उत्सुक है।

उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन इन राज्यों में भाजपा पहले से ही सरकार चला रही है। हालांकि, पंजाब एक अलग तरह की राजनीतिक चुनौती पेश करता है। दशकों तक भाजपा अपने पूर्व सहयोगी शिरोमणि अकाली दल की सहयोगी रही। अब पार्टी राज्य में एक स्वतंत्र राजनीतिक ध्रुव के रूप में उभरने के

लिए दृढ़ संकल्पित है।

इसका पहला बड़ा संकेत कुछ साल पहले वरिष्ठ पूर्व कांग्रेस नेता सुनील जाखड़ को भाजपा के पंजाब अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जाने से मिला। तब से, कांग्रेस और अन्य पार्टियों के कई प्रमुख नेता, जिनमें पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और रवनीत सिंह बिंदू शामिल हैं, या तो भाजपा में शामिल हो गए हैं या उसके साथ गठबंधन कर चुके हैं। बिंदू को बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। भाजपा की आक्रामक विस्तारवादी रणनीति अब पूरी तरह से सक्रिय है, जिसके तहत आम आदमी पार्टी से सात राज्यसभा सांसदों ने दल-बदल किया है। विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और अकाली दल से आने वालों का ‘खुले दिल से’ स्वागत करने की नीति स्पष्ट रूप से दिखाई देगी।

जैसे-जैसे भाजपा पंजाब विधानसभा चुनावों के लिए अपनी रणनीति को और मजबूत कर रही है, इस बात पर गहन अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या पार्टी मुख्यमंत्री पद के लिए किसी उम्मीदवार को मैदान में उतारेगी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशाल छाया में चुनाव लड़ेगी। दशकों तक पंजाब में भाजपा को मुख्य रूप से एक शहरी, गैर-सिख हिंदू पार्टी के रूप में देखा जाता था और यह अपने सहयोगी शिरोमणि अकाली दल पर निर्भर रही। लेकिन पार्टी नेताओं का मानना ​​है कि



राजनीतिक परिदृश्य में काफी बदलाव आया है। पिछले कुछ वर्षों में, भाजपा ने चुपचाप अपना सामाजिक आधार बढ़ाया है और प्रभावशाली सिख नेताओं, दलित चेहरों, जाट सिख प्रतिनिधियों और विभिन्न जाति समूहों के नेताओं को अपने साथ जोड़ा है। हाल ही में वरिष्ठ अधिवक्ता और जाने-माने मानवाधिकार कार्यकर्ता एचएस फूलका के इर्द-गिर्द चर्चाएं केंद्रित हैं। आम आदमी पार्टी में रहने के बाद भाजपा में शामिल होने से यह अटकलें तेज हो गई हैं कि वे पंजाब में पार्टी के एक प्रमुख चेहरे के रूप में उभर सकते हैं। हालांकि, भाजपा के अंदरूनी सूत्रों का कहना ​​है कि पार्टी द्वारा मुख्यमंत्री पद के किसी भी उम्मीदवार की आधिकारिक घोषणा करने की संभावना नहीं है। इसके बजाय, चुनाव मुख्य रूप से मोदी के नेतृत्व, शासन प्रणाली और राष्ट्रीय लोकप्रियता

के इर्द-गिर्द लड़े जाने की उम्मीद है, जिसमें प्रधानमंत्री पंजाब में भाजपा का निर्विवाद चेहरा बने रहेंगे।

अमृतसर संभवतः भारत का राजनीतिक रूप से सबसे उदार लोकसभा क्षेत्र है – एक ऐसा स्थान जहां चुनावी हार से करियर समाप्त नहीं होता, बल्कि अक्सर यह करियर को और भी ऊंचा उठाता है। एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था में, जो आमतौर पर हारने वालों के प्रति कठोर होती है, पंजाब को इस चर्चित सीट ने चुपचाप असाधारण रूप से सफल उम्मीदवारों को जन्म देने की प्रतिष्ठा अर्जित कर ली है।

2014 में, वरिष्ठ भाजपा नेता अरुण जेटली अमृतसर से चुनाव हार गए थे, लेकिन जल्द ही मोदी मंत्रिमंडल में सबसे शक्तिशाली मंत्रियों से से एक बनकर उभरे। यही सिलसिला 2019 में भी दोहराया गया जब पूर्व राजनयिक हर्दीप सिंह पुरी को लोकसभा चुनाव हारने के बावजूद केंद्र सरकार में तेजी से पदीन्नत किया गया और वे मोदी मंत्रिमंडल में एक प्रमुख मंत्री बने हुए हैं।

यह परंपरा पूर्व राजदूत तरनजीत सिंह संधू के साथ जारी रही। अमृतसर से 2024 के लोकसभा चुनाव में हार के बाद, संधू को अब दिल्ली का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है, जिससे इस निर्वाचन क्षेत्र की अनोखी

सनत जैन

विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया हालिया फैसला चुनाव आयोग के अधिकारों की पुष्टि करता है। इसके साथ ही इस फैसले से कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। अदालत ने चुनाव आयोग की कार्रवाई को वैधानिक अधिकारों के दायरे में माना, परंतु सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाई गई उन आशंकाओं और दस्तावेजी आपत्तियों पर फैसला स्पष्ट नहीं है, जिनका सीधा संबंध करोड़ों मतदाताओं के संवैधानिक अधिकारों से जुड़ा हुआ है। यही कारण है, यह विवाद समाप्त होने के बजाय और अधिक गहराने की आशंका पैदा होने लगी है। एसआईआर प्रक्रिया का मूल उद्देश्य मतदाता सूची को शुद्ध और सही करना बताया गया था। लेकिन व्यवहार में अनेक ऐसे मामले सामने आए हैं, जिनमें वैध दस्तावेज रखने वाले नागरिकों के नाम भी मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। बीएलओ रिटर्निंग अधिकारी के अधिकार भी चुनाव आयोग ने स्वयं इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं। मतदाता शुद्धिकरण के लिए केंद्रीय चुनाव आयोग के पोर्टल से बिना बीएलओ, बिना रिटर्निंग अधिकारी की जानकारी के बिना भौतिक सत्यापन के करोड़ों मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से अलग कर दिए गए। जिनके नाम 2003 की मतदाता सूची में मौजूद थे। उनके माता-पिता के नाम भी 2003 की मतदाता सूची में थे। उन्हें भी विभिन्न तकनीकी कारणों के आधार पर सूची से बाहर कर दिया गया। इससे प्रश्न उठना स्वाभाविक है, वर्षों से मतदान कर रहे नागरिकों की वैधता पर अचानक संदेह कर उनका नाम कैसे मतदाता सूची से हटाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में जनस्थली नागरिकता और मतदाता सूची की स्थिरता और विश्वसनीयता का आधार क्या रहेगा?

स्थिति की गंभीरता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब तक लगभग 5.50 करोड़ मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जाने की बात सामने आ रही है। अकेले पश्चिम बंगाल में लगभग एक करोड़ नाम मतदाता



सूची से हटाए जा चुके हैं, जबकि करीब 28 लाख लोगों ने दस्तावेजों के साथ टिब्यूनल में अपील कर रखी है। यह केवल चुनाव आयोग के अधिकारों से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। एसआईआर की प्रक्रिया में जिन मतदाताओं के नाम काटे गए हैं उनके संवैधानिक अधिकारों से जुड़ा हुआ मामला भी है। इतनी बड़ी संख्या मतदाता सूची से नाम काटना प्रशासनिक त्रुटि का संकेत नहीं है। बल्कि यह संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़े नागरिकों के अधिकार का प्रश्न है। एसआईआर की प्रक्रिया में यदि करोड़ों लोगों के संवैधानिक अधिकार खत्म हो रहे हैं। इस बारे में भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय स्पष्ट नहीं है। विधि विशेषज्ञों का कहना है सुप्रीम कोर्ट के आदेश में यह स्पष्ट नहीं किया गया, जिन लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं, उनके अधिकारों की सुरक्षा किस प्रकार सुनिश्चित होगी। बिहार और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों ने जिन लोगों के नाम मतदाता सूची में नहीं है उन्हें अभी तक जो सरकारी सुविधा मिल रही थी, वह बंद करने का निर्णय लिया है। इसमें जो मुसलमान मतदाता थे, उन्हें बांग्लादेशी और रोहिंया मुसलमान बताकर उनके लिए अलग से डिडेंशन सेंटर बनाकर रखने की बात की जा रही है। असम, पश्चिम बंगाल और बिहार की सरकार उन्हें अपना नागरिक मानने को तैयार नहीं है। इसको लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है जो धार्मिक धुवीकरण की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। चुनाव आयोग को लेकर कई गंभीर किस्म के आरोप लगाए जा रहे हैं। चुनाव आयोग की नियुक्ति कानून की सुनवाई भी सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। एसआईआर के जो नियम ज्ञानेश कुमार के चुनाव आयोग ने तैयार किये, हर राज्य में अलग-अलग तरह के नियम बनाए गए। इसको लेकर यह विवाद सुप्रीम कोर्ट में गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कई महीने तक प्रक्रिया को लेकर सुनवाई की, लेकिन इस संबंध में कोई भी स्पष्टता वाला

का आग्रह किया था। लेकिन इंडिया गठबंधन की कई पार्टियां कांग्रेस से नाराज हैं और दोनों पक्षों के बीच खाई चौड़ी होती जा रही है। इसलिए, ममता बनर्जी का यह कदम इंडिया गठबंधन की एकता बनाए रखने का एक तरीका हो सकता है और कांग्रेस शायद एक कदम पीछे हट गई हो। लेकिन इस तरह से नुकसान की भरपाई करने की कोशिश से विपक्ष को शायद ही कोई मदद मिलेगी क्योंकि राहुल गांधी अकेले दम पर ही आगे बढ़ना जारी रखे हुए हैं।

उत्तर प्रदेश के प्रभावशाली नौकरशाह संजय प्रसाद और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के बीच हुई गुप्त बैठक ने दिल्ली के सत्ता गलियारों में अटकलें का एक नया दौर शुरू कर दिया है। 1995 बैच के आईएएस अधिकारी प्रसाद मुख्यमंत्री योगी के कार्यालय, गृह, सूचना और सतर्कता विभाग का कार्यभार संभाल रहे हैं।

इस मामले में रहस्य तब और गहरा गया जब नबीन के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर मुलाकात की एक तस्वीर कुछ समय के लिए दिखी और अगले दिन गायब हो गई। प्रसाद के करीबी लोगों ने इस घटना को महज एक ‘शिष्टाचार भेंट’ बताकर टालने की कोशिश की है, लेकिन कुछ ही लोग ऐसा मानते हैं। प्रसाद और नबीन दोनों विहार से हैं। कहा जा रहा है कि प्रसाद राजनीति में उतरने के इच्छुक हो सकते हैं।

घुसपैठ : चुनौतियों के बीच राष्ट्रीय हित और सामाजिक विश्वास का सवाल

पवन

पिछले कई वर्षों में देश के विभिन्न हिस्सों, खासकर सीमावर्ती क्षेत्रों में आबादी की संरचना में आ रहे बदलावों की पृष्ठभूमि में केंद्र सरकार द्वारा उच्चाधिकार समिति का औपचारिक गठन राष्ट्रीय एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिहाज से एक महत्वपूर्ण व दूरदर्शी पहल है। इस मामले में केंद्रीय गृहमंत्री का यह कहना विचारणीय है कि घुसपैठ तथा किन्हीं अन्य वजहों से जनसंख्या में आने वाला असामान्य बदलाव किसी भी राष्ट्र के वर्तमान और भविष्य के लिए एक गंभीर चुनौती है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले वर्ष स्वतंत्रता दिवस के दिन इस उद्देश्य के लिए जल्द ही एक उच्चाधिकार समिति के गठन का एलान किया था।

उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ वर्षों में अवैध घुसपैठ पर चर्चाएं बढ़ी जरूर हैं, लेकिन इस समस्या की जड़ें काफी गहरी हैं। असम के पूर्व राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) एस्के सिन्हा ने 1998 में इस संबंध में एक विस्तृत रिपोर्ट तत्कालीन राष्ट्रपति को सौंपी थी, जिसके अनुसार बांग्लादेश से हो रही अवैध घुसपैठ ने असम की सीमा पर स्थित कई जिलों में आबादी का संतुलन बदल दिया है। 2005 में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वानंद सोनोवाल बनाम भारत संघ मामले में अवैध घुसपैठ की तुलना एक किस्म के अधोषिक्त बाहरी आक्रमण से की थी। राजनीतिक दलों में इस विषय पर मतभेद और बहसें बहने जारी हों, लेकिन तथ्य अपनी कहानी आप कहते हैं।

सेंटर फॉर पॉलिसी स्टडीज के एक शोध के



अनुसार, 1951 से लेकर 2011 के बीच, पश्चिम बंगाल में मुस्लिमों की आबादी पश्चिमी जिलों की तुलना में बांग्लादेश की सीमा से सटे जिलों में लगभग दोगुनी और कहीं-कहीं तो तीन गुनी रफ्तार से बढ़ी। यह प्रवृत्ति सिर्फ असम और पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं है। कुछ अध्ययन एवं सार्वजनिक विमर्श दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार जैसे देश के अन्य हिस्सों में भी जनसांख्यिकीय परिवर्तनों को लेकर चिंताओं के संकेत देते रहे हैं। हालांकि, शिक्षा का स्तर, स्वास्थ्य सेवा, रोजगार के अवसर, प्रवासन इत्यादि जैसे अनेक कारक जनसांख्यिकीय बदलाव को प्रभावित कर सकते हैं, पर अवैध घुसपैठ को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सही निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए नवगठित समिति की कार्यप्रणाली और उद्देश्य संतुलित होना ही जरूरी है। देश की सबसे बड़ी शक्ति उसकी विविधता और सामाजिक सह-अस्तित्व की परंपरा रही है। ऐसे में, नवगठित समिति की सफलता इसमें होगी कि वह तथ्यों, पारदर्शिता और संतुलित दृष्टिकोण के आधार पर ऐसी सिफारिशें दे, जो राष्ट्रीय हितों को मजबूत करने के साथ सामाजिक विश्वास को भी कायम रखें।

क्वाड ने हिंद प्रशांत में खींची नई रणनीतिक लकीर

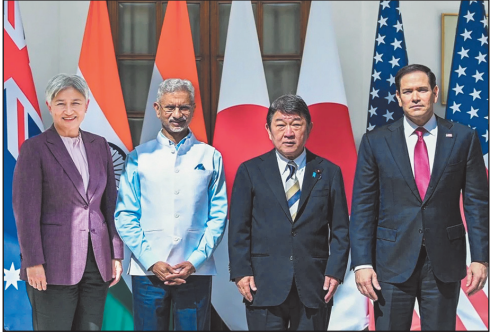
नीरज कुमार दुबे

दिल्ली में आयोजित क्वॉड विदेश मंत्रियों की बैठक ने साफ कर दिया है कि हिंद महासागर से लेकर दक्षिण चीन सागर तक अब शक्ति संतुलन की नई लकीर खिंच चुकी है। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने जिस आक्रामक रणनीतिक एकजुटता का प्रदर्शन किया है, वह चीन की विस्तारवादी चालों और वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं पर उसके शिकंजे के खिलाफ खुला मोर्चा है। नई दिल्ली में हुई इस बैठक ने यह संदेश दे दिया कि हिंद प्रशांत क्षेत्र को अब दबाव, धमकी और आर्थिक ब्लैकमेल से निर्यात्रित नहीं किया जा सकेगा।

क्वॉड की सबसे विस्फोटक घोषणा रही महत्वपूर्ण खनिज पहल ढांचा। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर लगभग बीस अरब डॉलर के निवेश समर्थन के साथ ऐसी आपूर्ति शृंखला खड़ी करने का फैसला किया है जो किसी एक देश, विशेषकर चीन, पर निर्भर न रहे। दुर्लभ खनिज आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर, रक्षा उत्पादन, विद्युत वाहन और आधुनिक हथियार प्रणाली की रीढ़ बन चुके हैं। चीन इन खनिजों की वैश्विक आपूर्ति पर वर्षों से दबदबा बनाए हुए है। ऐसे में क्वॉड का यह कदम सीधे तौर पर बीजिंग की आर्थिक और रणनीतिक ताकत को चुनौती देता है।

बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि खनन, प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण तक पूरी शृंखला को सुरक्षित और विविध बनाया जाएगा। केवल निवेश ही नहीं, बल्कि निर्यात श्रृंा एजेंसियों, विकास वित्त संस्थानों, बीमा, अनुदान और निजी पूंजी को भी इस रणनीति में शामिल किया जाएगा। इसका अर्थ है कि क्वॉड अब केवल सुरक्षा मंच नहीं, बल्कि वैश्विक आर्थिक शक्ति समूह के रूप में उभर रहा है।

समुद्री सुरक्षा के मोर्चे पर भी क्वॉड ने बड़ा दांव चला है। पहली बार हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग पहल शुरू की गई है, जिसके तहत चारों देश वास्तविक समय की सूचनाएं साझा करेंगे और समुद्री गतिविधियों पर संयुक्त निगरानी रखेंगे। इसका प्रारंभिक केंद्र हिंद महासागर क्षेत्र होगा। यह सीधे तौर पर चीन की समुद्री घुसपैठ, संदिग्ध जहाज गतिविधियों और दबाव की राजनीति को रोकने की तैयारी है।



दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर को लेकर संयुक्त बयान का स्वर असाधारण रूप से कठोर रहा। क्वॉड देशों ने साफ कहा कि बल प्रयोग, डराने धमकाने की नीति, जल तोपों का इस्तेमाल, जहाजों को टक्कर मारना और सैन्यीकरण क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा है। यह बिना नाम लिए चीन को सीधी चेतावनी थी। खास बात यह रही कि चारों देशों ने अंतरराष्ट्रीय कानून और समुद्री स्वतंत्रता की रक्षा को अपनी साझा प्रतिबद्धता बताया।

ऊर्जा सुरक्षा को लेकर भी क्वॉड ने बड़ा रणनीतिक मोर्चा खोला है। तेल, गैस, उर्वरक और ऊर्जा बाजार में वैश्विक अस्थिरता के बीच चारों देशों ने हिंद प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा पहल की घोषणा की। इसका मकसद ऊर्जा आपूर्ति को सुरक्षित रखना, समुद्री व्यापार मार्गों की रक्षा करना और आपातकालीन परिस्थितियों में सहयोग बढ़ाना है। यह पहल केवल आर्थिक नहीं, बल्कि सामरिक महत्व भी रखती है क्योंकि पश्चिम एशिया से हिंद महासागर तक ऊर्जा मार्गों पर बढ़ते तनाव का सीधा असर एशिया की अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ता है।

क्वॉड ने समुद्र के नीचे बिछी डिजिटल केबल प्रणाली की सुरक्षा को भी प्राथमिकता दी है। प्रशांत द्वीपीय देशों को सुरक्षित समुद्री केबल नेटवर्क से जोड़ने का लक्ष्य तय किया गया है। यह चीन की डिजिटल घेराबंदी और तकनीकी प्रभाव को संतुलित करने की कोशिश मानी जा रही है। साथ ही पांचवीं और छठी पीढ़ी की संचार प्रणाली, खुली नेटवर्क व्यवस्था और डिजिटल पहचान मानकों पर सहयोग का फैसला यह दर्शाता है कि भविष्य की तकनीकी

जंग में भी क्वॉड साझा मोर्चा बना रहा है।

आतंकवाद के खिलाफ बयान भी बेहद स्पष्ट रहा। पहलगाम हमले का उल्लेख करते हुए क्वॉड देशों ने सीमा पार आतंकवाद की निंदा की और कहा कि आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता ही एकमात्र रास्ता है। यह भारत के लिए बड़ी कूटनीतिक सफलता मानी जा रही है क्योंकि इससे पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक समर्थन मजबूत होता दिखाई देता है।

भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बैठक के बाद साफ कहा कि हिंद प्रशांत आने वाले समय में वैश्विक व्यापार, ऊर्जा और समुद्री वाणिज्य का केंद्र बनने जा रहा है, इसलिए क्वॉड की जिम्मेदारियां भी तेजी से बढ़ेंगी। उनका संदेश साफ था कि अब यह मंच केवल विचार विमर्श तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जमीन पर असर दिखाने वाली ताकत बन जाएगी।

देखा जाये तो नई दिल्ली की इस बैठक ने यह स्थापित कर दिया है कि दुनिया अब दो स्पष्ट ध्रुवों की ओर बढ़ रही है। एक ओर वे ताकतें हैं जो नियम आधारित व्यवस्था, स्वतंत्र समुद्री व्यापार और संतुलित आर्थिक ढांचे की बात कर रही हैं, जबकि दूसरी ओर विस्तारवाद, दबाव और आर्थिक नियंत्रण की राजनीति है। क्वॉड ने अपने फैसलों से यह संकेत दिया है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में अब चीन की मनमानी को खुली चुनौती दी जाएगी।

बहरहाल, दिल्ली में संपन्न क्वॉड बैठक केवल एक कूटनीतिक आयोजन नहीं थी, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस. जयशंकर की आक्रामक और दूरदर्शी विदेश नीति का शक्तिशाली प्रदर्शन भी थी। जिस तरह भारत ने अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया को एक साझा रणनीतिक मंच पर मजबूती से संगठित किया, उसने यह साबित कर दिया कि नई दिल्ली अब वैश्विक शक्ति संतुलन की निर्णायक धुरी बन चुकी है। चीन की आर्थिक दबंगई, समुद्री विस्तारवाद और आपूर्ति शृंखलाओं पर उसके नियंत्रण को चुनौती देने के लिए दिल्ली में जो रणनीति तैयार हुई, वह आने वाले वर्षों में हिंद प्रशांत की दिशा तय करेगी। मोदी और जयशंकर की जोड़ी ने यह संदेश पूरी दुनिया को दे दिया है कि भारत वैश्विक समीकरण बदलने वाला नेतृत्वकर्ता है।

बंगाल में शुरुआत हो चुकी है बदलाव की

अवधेश कुमार

पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी सरकार द्वारा सत्ता संभालने के अल्पकाल में ही स्पष्ट बदलाव दिख रहा है। ममता सरकार की विचारधारा और दिशा के बिल्कुल उलट शुभेंदु सरकार के शासन की गाड़ी तीव्र गति से वहां पहुंच रही है, जहां से बंगाल शांत और स्थिर हो सामान्य राज्य के रूप में गतिविधियों का निर्धारण करे। शुभेंदु सरकार ने केंद्रीय योजनाओं को लागू करने के अलावा कुछ ऐसे फैसले लिए, जिनसे बदलाव आया। क्या किसी ने कल्पना की थी कि सरकार बनने के हफ्ते भर के अंदर ही राज्य से तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) द्वारा लगाए गए अवैध दोष ब्रथ हट जाएंगे, बैरिकेड समाप्त हो जाएंगे, अवैध वसूली का धंधा खत्म हो जाएगा? लेकिन यह सब हो गया। ममता ने महिलाओं को रात में न निकलने की बात कही थी। सरकार बदलते ही अब महिलाएं देर रात तक बेखौफ होकर बाहर निकल सकती हैं। सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। कोलकाता से आसनसोल तक अवैध निर्माण के विरुद्ध बुलडोजर कार्रवाई का हिंसक विरोध पूर्व सरकार की तस्वीर पेश कर रहा था। पत्थरबाजी भी हुई। इसके बाद फुटेज से पत्थरबाजों और दंगाइयों की पहचान करके कार्रवाई हो रही है तथा पुलिस ने एलान किया है कि जिन लोगों ने हिंसा और तोड़फोड़ की है, उनकी संपत्ति से इसकी वसूली की जाएगी। भाजपा ने चुनाव प्रचार के दौरान कानून-व्यवस्था मजबूत करने, महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने, अवैध घुसपैठ रोकने और घुसपैठियों को बाहर निकालने, सीमा व आंतरिक सुरक्षा की मजबूती, तृष्टीकरण के खात्मे, हिंदुओं के साथ हुए अन्याय को दूर करने, भ्रष्टाचार खत्म करने जैसे वादे किए थे। इसी क्रम में, मुख्यमंत्री का पदभार संभालते ही शुभेंदु अधिकारी ने बांग्लादेश की सीमा पर घेराबंदी के लिए सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) को भूमि सौंपने का आदेश दिया। सबसे बड़ा व अहम फैसला नेशनल हाईवे 10 व 110 के सात हिस्से केंद्र सरकार को सौंपना है। इनमें से पांच सड़कें चिकन नेक,

का आग्रह किया था।

लेकिन इंडिया गठबंधन की कई पार्टियां कांग्रेस से नाराज हैं और दोनों पक्षों के बीच खाई चौड़ी होती जा रही है। इसलिए, ममता बनर्जी का यह कदम इंडिया गठबंधन की एकता बनाए रखने का एक तरीका हो सकता है और कांग्रेस शायद एक कदम पीछे हट गई हो। लेकिन इस तरह से नुकसान की भरपाई करने की कोशिश से विपक्ष को शायद ही कोई मदद मिलेगी क्योंकि राहुल गांधी अकेले दम पर ही आगे बढ़ना जारी रखे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के प्रभावशाली नौकरशाह संजय प्रसाद और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के बीच हुई गुप्त बैठक ने दिल्ली के सत्ता गलियारों में अटकलें का एक नया दौर शुरू कर दिया है। 1995 बैच के आईएएस अधिकारी प्रसाद मुख्यमंत्री योगी के कार्यालय, गृह, सूचना और सतर्कता विभाग का कार्यभार संभाल रहे हैं।

इस मामले में रहस्य तब और गहरा गया जब नबीन के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर मुलाकात की एक तस्वीर कुछ समय के लिए दिखी और अगले दिन गायब हो गई। प्रसाद के करीबी लोगों ने इस घटना को महज एक ‘शिष्टाचार भेंट’ बताकर टालने की कोशिश की है, लेकिन कुछ ही लोग ऐसा मानते हैं। प्रसाद और नबीन दोनों विहार से हैं। कहा जा रहा है कि प्रसाद राजनीति में उतरने के इच्छुक हो सकते हैं।

जानें क्या है मयूरासन और इसके लाभ



मयूरासन यानी मयूर की तरह किया जाने वाला आसन। योगा में यह वह आसन है जिसमें आपका शरीर मयूर की तरह दिखाई पड़ता है। इस आसन को करने के लिए बहुत सावधानियां बरतने की आवश्यकता होती है। इस आसन में शरीर का पूरा भार हाथों पर टिका होता है और शरीर हवा में लहराता है। मयूरासन के भी कई लाभ हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि मयूरासन कैसे किया जाए। मयूरासन के लाभ क्या हैं। मयूरासन करने की विधि क्या है। मयूरासन कब करना चाहिए। इत्यादि सवालों के जवाब जानने के लिए यह जानना जरूरी है कि मयूर आसन क्या है।

मयूरासन करने की विधि

मयूरासन खुली हवादार जगह में करना चाहिए। इसके लिए आप सबसे पहले घुटनों के बल बैठ जाएं और आगे की ओर झुके। आगे झुकते हुए दोनों हाथों की कोहनियों को मोड़कर नाथि पर लगाकर जमीन पर सटा लें। इसके बाद अपना संतुलन बनाते हुए घुटनों को धीरे-धीरे सीधा करने की कोशिश करें। अब आपका शरीर पूरी सीध में है और सिर्फ आपके हाथ जमीन से सटे हुए हैं। इस आसन को करने के लिए शरीर का संतुलन बनाए रखना जरूरी है जो कि पहली बार में संभव नहीं। यदि आप रोजाना मयूर आसन का अभ्यास करेंगे तो आप निश्चित तौर पर आसानी से इसे कर पाएंगे।

मयूरासन के दौरान सावधानी

मयूरासन करते हुए बहुत सावधानी की जरूरत पड़ती है, इसीलिए आप जब भी मयूरासन करें तो किसी योग एक्सपर्ट की देखरेख में करें या फिर पहले इस आसन को करने की विधि को अच्छी तरह से जानें। तभी आप मयूर आसन को सही तरह से कर पाएंगे और इसका भरपूर लाभ उठा पाएंगे।



मयूरासन के लाभ

- मयूरासन के कई लाभ हैं। आमतौर पर मयूरासन से गुर्दे, अनाशय और आमाशय के साथ ही युक्त इत्यादि को बहुत लाभ होता है।
- चेहरे पर चमक लाने के लिए मयूरासन करना चाहिए। मयूरासन करने से हाथ, पैर व कंधे की मांसपेशियों में मजबूती आती है। जिन लोगों को बहुत अधिक कब्ज रहती है उनके लिए मयूरासन से बढ़िया कोई उपाय नहीं। मधुमेह के रोगियों के लिए भी यह आसन लाभकारी है।
- यदि आपको आंखों संबंधी कोई समस्या है तो उसका निदान भी मयूरासन से किया जा सकता है।
- पाचन क्रिया को सुचारु रूप से चलाने के लिए मयूरासन करना चाहिए। यदि आपको पेट संबंधी समस्याएं जैसे गैस बनना, पेट में दर्द रहना, पेट साफ ना होना इत्यादि होता है तो आपको मयूरासन करना चाहिए।
- सामान्य रोगों के अलावा मयूर आसन से आंतों व अन्य अंगों को मजबूती मिलती है। मयूरासन से आमाशय और मूत्राशय के दोषों से मुक्ति मिलती है।

किसे नहीं करना चाहिए

- आमतौर पर मयूरासन उन लोगों को करने के लिए मना किया जाता है जो उच्च रक्तचाप की समस्या से पीड़ित हैं।
- टी.बी यानी तपेदिक के मरीजों को भी मयूरासन नहीं करना चाहिए।
- हृदय रोग या हार्ट की बीमारियों से ग्रसित लोगों को भी मयूरासन नहीं करना चाहिए। अल्सर और हर्निया रोग से पीड़ित लोगों को भी मयूरासन करने से बचना चाहिए।

दाढ़ी मूँछ के भी हैं ढेरों फायदे

आप विश्वास नहीं करेंगे लेकिन वैज्ञानिक तक मान चुके हैं कि दाढ़ी रखने से त्वचा का कैंसर नहीं होता। दरअसल सूर्य की अल्ट्रावाइलेट किरणें स्किन कैंसर का कारण बनती है। शोध के



मुताबिक लोग दाढ़ी रखते हैं वे 90 फीसदी तक यूवी किरणों से अपने आपको बचाने में कामयाब रहते हैं। है ना स्किन कैंसर से बचने का बढ़िया उपाय। क्लनीन शेव लोगों की तुलना में दाढ़ी मूँछ रखने वाले लोगों की अस्थमा और एलर्जी की शिकायत कम होती है। दरअसल प्रदूषित होते वातावरण में दाढ़ी मूँछ धूल और प्रदूषण को सीधे चेहरे और मुंह के संपर्क में नहीं आने देती। दाढ़ी और मूँछ के बाल छलनी की तरह काम करके प्रदूषित कणों को रोक लेते हैं। ये ठीक वही काम करती है जो आंखों के लिए पलक और नाक के बाल करते हैं। दाढ़ी मूँछ रखने वालों की स्किन आमतौर पर झाड़ नहीं मिलेगी। दरअसल दाढ़ी मूँछ होने से चेहरे पर रोजमर्रा की फेसक्रीम का दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। दाढ़ी मूँछ चेहरे को जवान बनाए रखते हैं क्योंकि इससे त्वचा पर नमी बनी रहती है। दाढ़ी मूँछ रखने वाले लोग चेहरे से आमतौर पर जवान दिखते हैं क्योंकि उनकी दाढ़ी मूँछ उनके चेहरे पर पड़ने वाली झुर्रियों को छिपा लेती है। रोज रोज शेव करने से स्किन कटने फटने का डर रहता है और त्वचा पर संक्रमण का भी खतरा रहता है लेकिन दाढ़ी मूँछ रखने से ये झंझट और संक्रमण का खतरा भी नहीं रहता।

विविध



हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां, लेकिन फिर भी कम निकले... आज युवाओं की कई ख्वाहिशें हैं। खासतौर पर युवा आजादी चाहता है। आज के दौर में युवाओं की सोच में क्रांति और आजादी की बातें उभरकर सामने आ रही हैं। आखिर देश का युवा किन बातों से आजादी चाहता है, यही जानने की कोशिश है यह आलेख।

हर ख्वाहिश पर दम निकले...

माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला सात महीने में तीसरी बार भारत की विजिट पर आए हैं। वे सोमवार को दिल्ली में माइक्रोसॉफ्ट के इवेंट में ऐड्रेस करने पहुंचे। गालिब के शेर से शुरुआत की। उन्होंने कहा कि जब आप दुनिया को देखने का नजरिया बदल लेते हैं, तो आप दुनिया को भी बदल पाते हैं। एक वाक्ये का जिक्र करते हुए सत्या ने गालिब का शेर पढ़ा-**हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां मगर फिर भी कम निकले।** उनके इस अंदाज पर काफी देर तक हाल तालियों से गूंजता रहा। उन्होंने गालिब का यह शेर जिस भी संदर्भ में सुनाया हो लेकिन यह शेर आज के दौर में देश के युवाओं के लिए कुछ खास है। भारत में दुनिया की सबसे ज्यादा युवा आबादी बसती है। इस देश में करीब 30.56 करोड़ युवा बसते तो हैं लेकिन शायद बहुत कम युवाओं की ख्वाहिशें पूरी हो पाती हैं। यहां हम युवाओं की व्यक्तिगत ख्वाहिशों की बात नहीं कर रहे। यहां युवाओं की समग्र ख्वाहिशें हैं। आज देश का युवा आजादी चाहता है। यही उसकी ख्वाहिश है। आइए देखते हैं किन मुद्दों से भारतीय युवा को आजादी चाहिए...

जबरन करियर से आजादी

देश के ज्यादातर युवा इस मुश्किल से जूझ रहे हैं। 18 साल की उम्र तक पहुंचते ही उन पर करियर को लेकर सवालों की झड़ी लगा दी जाती है और आखिर में उन पर जबरन कुछ भी थोप दिया जाता है। ज्यादातर मां-बाप बच्चे की ख्वाहिश पूछे बिना ही उसे इंजीनियर या डॉक्टर बनने के लिए मजबूर करते हैं।

ऑनर किलिंग से आजादी



देश के कई हिस्सों में खाप जैसी पंचायतों के तुगलकी फरमान युवाओं की इच्छा के आड़े आते हैं। खास तौर पर हरियाणा में खाप का असर ज्यादा है। जहां जरा सी बात पर लोग आत्म सम्मान के नाम पर युवक-युवतियों को मार देते हैं। कई मामलों में लड़के लड़की दोनों की हत्या कर दी कई। समलैंगिकता, प्रेम विवाह, अपनी मर्जी से लड़का या लड़की चुनना ये सारी बातें खाप के नियमों के खिलाफ मानी जाती हैं, जिनसे मुक्ति जरूरी है। यही नहीं, पुलिस भी ऐसे कामों में तुगलकी फरमान सुनाती है।

लिंग भेद से आजादी

लिंग भेद से आजादी ऐसी आजादी है जिसके लिए हर लड़की जन्म लेने के साथ ही लड़ना शुरू कर देती है। घर में ज्यादा तवज्जी न मिलने से लेकर अपनी मर्जी के कपड़े न पहन पाने तक, लड़कियों को कई सारी मुश्किलें झेलनी



पड़ती हैं। यहां तक कि शादी करने में भी उनकी पसंद का ख्याल नहीं रखा जाता।

अपने नजरिये की आजादी



लोकतंत्र में रहने के चलते हर किसी को अपना नजरिया रखने की आजादी होनी चाहिए लेकिन भारत ऐसा देश है जहां अपनी बात रखना आपके लिए मुसीबत बन सकता है। सोशल मीडिया ने इस वॉर को और बढ़ाया है। भीड़ से अलग हटकर अगर आप अपना नजरिया पेश करते हैं तो किसी न किसी राजनीतिक पार्टी या उसके समर्थकों के शिकार बन जाते हैं।

सुरक्षा की चिंता से आजादी

हर मां-बाप अपने बच्चे को सुरक्षित देखना चाहते हैं लेकिन वे इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं कि घर की चारदीवारी में कैद करके बच्चों को सुरक्षित नहीं रखा जा सकता। खासकर लड़कियों के मामले में परिजन ज्यादा सख्त होते हैं। उनके घर से निकलने और घर लौटने के समय को लेकर वो ज्यादा चिंतित होते हैं क्योंकि उन्हें उत्पीड़न, अपहरण या हत्या जैसी वारदातों का डर सलाता रहता है।

इस्तेमाल होने से आजादी

हर युवा अपने उज्ज्वल जीवन की ख्वाहिश रखता है। युवा जब देखता है कि केवल योग्यता और ईमानदारी से कार्य संभव नहीं, तो कुंठाग्रस्त होकर गलत रास्तों पर चल पड़ता है। निश्चित तौर पर ऐसे में ही समाज के दुश्मन उनकी भावनाओं को भड़काकर व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह के लिए प्रेरित करते हैं, फलतः अपराध और आतंकवाद का जन्म होता है। युवाओं को मताधिकार तो दे दिया गया है पर उच्च पदों पर पहुंचने और निर्णय लेने के उनके स्वप्न को दमित करके उनका इस्तेमाल नेताओं द्वारा सिर्फ अपने स्वा्थ में किया जा रहा है।



सवाल सिर्फ युवा शक्ति के भटकाव का नहीं है, वरन अपनी संस्कृति, सभ्यता, मूल्यों, कला एवम् ज्ञान की परंपराओं को भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखने का भी है। युवाओं को भी ध्यान देना होगा कि कहीं उनका उपयोग सिर्फ मोहरों के रूप में न किया जाय।

ऑनलाइन रहना क्यों पसंद...?

इंटरनेट के माध्यम से अब दुनिया के किसी भी भाग से आसनी से संपर्क बनाया जा सकता है। लोग अब घर बैठे ही दुनियाभर में अपने दोस्त

बनाने लगे हैं, और ऑनलाइन रहकर ही प्यार ,डेटिंग, और शादी के लिए जोड़े भी खोजे जाने लगे हैं। ऑनलाइन दोस्ती के बहुत से नुकसान भी होते हैं, जैसे आप जिससे दोस्ती कर रहें हैं वह वास्तव में आपने बारे में सारी बातें सच बता रहा है, या आपको धोखा देने के मकसद से झूठी बातें बता रहा है। आप उसे सामने से नहीं देख सकते इसलिए आप उसकी वास्तविकता भी नहीं जान सकते हैं। ऑनलाइन चैटिंग से होने वाले इन नुकसानों के बावजूद क्यों हम इसका इस्तेमाल करना जारी रखते हैं?

गुप्त नाम का फायदा

ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ा फायदा है नाम को गुप्त रखने की आजादी। आप किसी भी नाम और किसी भी फोटो के साथ अपनी एक प्रोफाइल बना सकते हैं, कम्प्यूटर यह नहीं समझ पायेगा कि, आप झूठ बोल रहे हैं। आप किसी से या हर किसी से बात कर सकते हैं, और आपके वास्तविक जीवन की बुराई या कमियां जैसे, आपकी क्या हैसियत है ,और आप की योग्यता आदि कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता।



दुनियाभर में पहुंच

बहुत से देशों में जहां लड़के लड़कियां आपस में मिल कर बात नहीं कर सकते, उन स्थानों में लोग बातें करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफार्म का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरह से किसी एक देश में बैठा युवा दूसरे देश में अपने लिए दोस्त या जीवनसाथी की तलाश करके बातें कर सकता है।

सुविधाजनक

यूं तो यदि आपको किसी से मिलना जरूरत होती है,और फिर किसी अच्छी जगह की तलाश करनी होती है आदि। लेकिन आपको ऑनलाइन चैटिंग के लिए सिर्फ एक इंटरनेट पैक और अच्छे ब्राउजर के अलावा ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। इसलिए लोग इन सब की तुलना में ज्यादा सुविधाजनक-ऑनलाइन चैटिंग को वरीयता देते हैं।

दोषारोपण से आजादी

युवा व्यवहार मूलतः एक शैक्षणिक, सामाजिक, संरचनात्मक और मूल्यपरक समस्या है जिसके लिए राजनैतिक, सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक सभी कारक जिम्मेदार हैं। ऐसे में समाज के अन्य वर्गों को भी जिम्मेदारियों का अहसास होना चाहिए, सिफ4 युवाओं को दोष देने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि

बटन से कंट्रोल

हम ऑनलाइन कैसे दिखाई देते हैं इसका नियंत्रण हम सिर्फ एक बटन विलक कर के कर सकते हैं। सेल्फी कैमरे के साथ स्मार्टफोन और लाखों फिल्टर से हम अपनी एक नकली इमेज आसानी से बना सकते हैं। कई बार तो लोगों को अपनी यह इमेज अपनी असली इमेज से ज्यादा पसंद आने लगती है, और इसलिए वे ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन गप्पण और बातचीत में विपके रहते हैं। हम क्या कहते हैं, और किससे कहते हैं, इसका नियंत्रण भी खुद कर सकते हैं। इसके साथ यह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के उपयोग की इच्छा को भी बढ़ाता है।



मशहूर ब्रांड नेम्स की कहानी...

जहां तक ब्रांड की बात है ब्रांड और कुछ नहीं होता है सिर्फ कंपनी की अपनी एक पहचान होती है। कुछ ब्रांड ऐसे भी हैं जो कई कंपनियों के उत्पादों की पहचान बन गए हैं। क्या कभी आपने सोचा है की किसी भी ब्रांड का नाम आखिर कैसे बनाया जाता है और आज के मशहूर ब्रांड्स के नाम किस प्रकार से बनें हैं। नाईक एक मशहूर ब्रांड है। इसका नाम एक ग्रीक देवी के नाम पर पड़ा है जो की विजय की देवी मानी जाती है और इस ब्रांड का चिन्ह उनकी उड़ान का प्रतीक है। बात कोको कोला की करें तो पता चलता है कि असल में इस पेय पदार्थ की मुख्य सामग्री कोला बेरिज और कोको की पत्तियां है इसलिए ही इसको कोको कोला नाम दिया गया है। ऐसे ही पेप्सी नाम एक पाचक एंजाइम पेप्सिन से लिया

गया है, हालांकि यह पेप्सी में नहीं होता है। एडिडास ब्रांड का नाम इसके मालिक और निर्माता अडोल्फ डैस्लेटर के नाम पर रख गया है असल में अडोल्फ का उपनाम एडि था। अमेजन ब्रांड के मालिक सीईओ जेफ बेजोस अपनी इस कंपनी का नाम ए शब्द से शुरू होने वाला ही रखना चाहते थे और वो चाहते थे की उनकी कंपनी में दुनिया का हर सामान बिके इसलिए उन्होंने इसका नाम चुनने के लिए उन्होंने सबसे बड़ी नदी का नाम चुना। सोनी ब्रांड का नाम लैटिन शब्द 'सोनिअ' से लिया गया है जिसका अर्थ होता है आवाज। वोडाफोन का मतलब आसान शब्दों में हैं वॉइस डाटा टेलीफोन है। नीविया ब्रांड नेम लैटिन शब्द 'निवेअस' से बना है जिसका अर्थ होता है बर्फ जैसा सफेद।

आधा घंटा बंद रखें स्मार्टफोन...



आज के दौर में स्मार्ट फोन हमारी जरूरत बन गया है। सभी युवाओं के पास स्मार्टफोन मौजूद हैं। इसके कई फायदे भी हैं। स्मार्टफोन से न सिर्फ हमें जरूरी जानकारीया मिल जाती हैं, बल्कि यह मित्रों को भी हमारे साथ जोड़े रखने का काम करता है। स्मार्ट फोन की कई खूबियों के बारे में तो हम जानते भी नहीं हैं। वही इस स्मार्ट फोन के कुछ नुकसान भी हैं। स्मार्टफोन के जानकारों का कहना है कि अगर स्मार्ट फोन को दिन में आधे घंटे भी बंद रखा जाए तो इससे कई सारे फायदे मिल सकते हैं। आज हम आपको इन्हीं फायदों के बारे में बता रहे हैं।

दिमाग को मिलेगा रेस्ट

दिमाग असल में कई कामों को करने में व्यस्त रहता है। इन कामों को करने में वह तेजी से थकता है। ऐसे में आप अपना स्मार्ट फोन करीब आधा घंटा बंद रख सकते हैं। इससे आपके दिमाग को भी रेस्ट मिलेगा और वह भी तेजी से काम कर सकेगा।

ओवरहीटिंग से बचेगा

कई बार हमारा स्मार्ट फोन ओवरहीट हो जाता है। इसके हीट होने के वैसे तो और भी कई कारण हो सकते हैं। आपका फोन जब भी ओवरहीट हो जाए ऐसी स्थिति में आपको इसे कुछ देर के लिए बंद कर देना चाहिए। यही आपके पास पहला विकल्प है। इसके बाद इसकी समस्या को हल करने पर दिखा लीजिए।

समाधान जल्दी

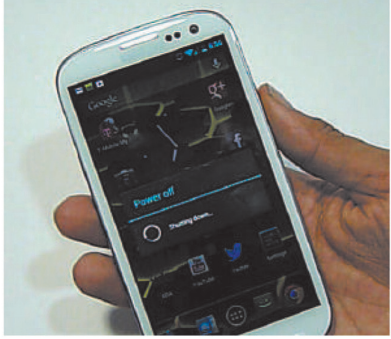
हर समय फोन से चिपके रहने से दिमाग कई तरह की समस्या का समाधान सही तरीके से नहीं कर पाता है। ऐसी स्थिति में फोन से थोड़े समय की दूरी बनाना आपके लिए हर समस्या का हल ढूढने के लिए बेहतर हो सकता है। ब्रेन को आराम मिलने से यह सही ढंग से काम करने के काबिल हो जाता है।

काम में लगता है मन

एक रिसर्च में पाया गया है कि करीब 61 प्रतिशत लोग हर समय नोटिफिकेशन देखते रहते हैं। नोटिफिकेशन न आने की स्थिति में भी लोगों को लगता है कि कोई नोटिफिकेशन आया है। ऐसे में वह व्यक्ति अपने काम पर फोकस नहीं कर पाता। स्मार्ट फोन को बंद करने से काम पर फोकस हो पाता है और वह अच्छी तरह से किया जाता है।

रीबूट करने का फायदा

स्मार्टफोन कई बार हैंग होने लगता है। कई सारी ऐस बैकग्राउंड पर चलने से और मेमोरी ज्यादा यूज होने के कारण फोन हैंग करने लगता है। ऐसी स्थिति में आप अपना फोन रीबूट कर सकते हैं। रीबूट करने से फोन दोबारा से सही चलने लगता है।



साथियों का दबाव

जब ऑनलाइन प्लेटफार्म की शुरुआत हुई तो इसके फायदे सभी पता चले होंगे जब किसी ने पहली बार इसका उपयोग किया होगा। पहले तो हमें इसपर बात करने की आदत नहीं पड़ी थी। फिर इसका चलन बढ़ने के साथ साथियों का दबाव भी इस प्लेटफार्म का इस्तेमाल करने के लिए महसूस किया जाने लगा, और ये भी एक बड़ा कारण था कि युवा एक दूसरे को ऑनलाइन प्लेटफार्म का इस्तेमाल करते देख इसकी ओर आकर्षित होने लगे। अपनी उपलब्धियों और कहानियों को एक दूसरे से शेयर करने लगे। इस प्रकार एक यह ऐसा चक्र बन गया जो कभी कभी बहुत ज्यादा दोषपूर्ण बन जाता है। ऑनलाइन प्लेटफार्म के अधिक उपयोग से हम बिना किसी अनुशासन और नियंत्रण के चैटिंग करते हैं। जिससे हम असभ्य और अविवेकी बन सकते हैं। कई बार तो लोग किसी बहकावे में आकर उनका शिकार भी बन जाते हैं। इसलिए ऑनलाइन प्लेटफार्म का उपयोग करते समय हमें अधिक सतर्कता और संयम की आवश्यकता है।

मशहूर शायर बशीर बद्र का 91 वर्ष में निधन

भोपाल। निधन हो गया।वे 91 वर्ष के थे और लंबे समय से डिमेंशिया बीमारी से पीड़ित थे। परिवार सूत्रों के अनुसार उन्होंने गुरुवार दोपहर लगभग 12 बजे अंतिम सांस ली। उनके परिवार में पत्नी राहत और पुत्र तैयब हैं। पिछले काफी समय से उनकी स्मरण शक्ति कमजोर हो गई थी और वे लोगों को पहचानने में भी असमर्थ हो गए थे। बशीर बद्र ने उर्दू गजल को नया अंदाज और सरल भाषा दी। उनकी शायरी में मोहब्बत, जिंदगी, दर्द और सामाजिक संवेदनाओं की झलक दिखाई देती थी। उनके कई शेर देशभर में लोकप्रिय हुए। ‘उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए’ और ‘लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में’ जैसे शेर आज भी लोगों की जुबां पर हैं।इन्होंने वर्ष 1969 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की थी। बाद में वे मेरठ कॉलेज के उर्दू विभाग में व्याख्याता रहे।

साढे 18 लाख छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ हुआ: राहुल

नईदिल्ली। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सीबीएसई परीक्षा में कथित गड़बड़ियों को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर जमकर निशाना साधा और आरोप लगाया कि इसकी वजह से साढ़े 18 लाख छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ किया गया है। श्री गांधी ने कहा , धर्मेंद्र प्रधान जी, आप मुझ पर जितना हमला करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन इससे आपके अपराध कम नहीं होंगे। न ही इससे मैं 18.5 लाख बच्चों के लिए जवाब मांगना बंद करूंगा। उन्होंने सवाल किया कि सीबीएसई के ओएसएम कॉन्ट्रैक्ट को कॉइम्प्ट कंपनी को क्यों दिया गया, जो अपने पुराने नाम ग्लोबरेना के तहत पहले से विवादों में रही है। उन्होंने पूछा कि यह फैसला किसके आदेश पर लिया गया और कंपनी का बैकग्राउंड चेक क्यों नहीं किया गया। इसके साथ ही उन्होंने कॉइम्प्ट प्रबंधन और मोदी सरकार के बीच संबंधों पर भी सवाल खड़े किए।उन्होंने कहा , या तो सरकार ने बैकग्राउंड चेक किया और फिर भी कंपनी को काम दिया।

आम जनता का मार्गदर्शक बने पुलिस: मुर्मु

नईदिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने पुलिस से नागरिकों के मार्गदर्शक की भूमिका अपनाने पर जोर देते हुए कहा है कि इससे जनता और पुलिस के बीच विश्वास मजबूत होगा तथा लोग बिना किसी डर के शिकायत दर्जा करा सकेंगे।श्रीमती मुर्मु ने गुरुवार को गंगटोक में सिक्रिम पुलिस को १%भारत के राष्ट्रपति का पुलिस कर्मक प्रदान करने के अवसर पर यह बात कही।उन्होंने कहा कि भारत की पुलिस व्यवस्था पर औपनिवेशिक शासन की लंबी छाप रही है। उस समय पुलिस का प्राथमिक उद्देश्य जनता की सेवा करना नहीं, बल्कि उन्हें नियंत्रित करना और शासक व्यवस्था के आदेशों को सख्ती से लागू करना था। परिणामस्वरूप, पुलिस व्यवस्था के भीतर एक औपनिवेशिक मानसिकता ने जड़ जमा ली थी।इन्होंने कहा कि यह मानसिकता अब बदल रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए इस औपनिवेशिक दृष्टिकोण को पूरी तरह से छोड़ना होगा।

भारत और चीन ने सीमा पर स्थिति की समीक्षा की

नयी दिल्ली। भारत और चीन ने पिछले कुछ समय से सीमा पर सौहार्द की स्थिति बनाए रखने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए दोनों देशों के बीच चीन में विशेष प्रतिनिधियों की बैठक बुलाने पर सहमति व्यक्त की है।दोनों देशों के बीच विशेष प्रतिनिधि स्तर की पिछली वार्ता गत वर्ष अगस्त में हुई थी। दोनों पक्षों ने बुधवार को चीन में बातचीत के दौरान सीमा पर स्थिति की व्यापक समीक्षा की।विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि भारत-चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्य तंत्र की 35वीं बैठक बुधवार को बीजिंग में हुई जिसमें भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संयुक्त सचिव (पूर्वी एशिया) सुजीत घोष ने और चीनी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व चीनी विदेश मंत्रालय के सीमा और महासागरीय मामलों के विभाग की महानिदेशक सुथ्री होउ यानकी ने किया। मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा कि दोनों पक्षों के बीच रचनात्मक और भविष्योन्मुखी चर्चा के दौरा सीमा क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा की गयी। उन्होंने सीमा क्षेत्रों में शांति और सौहार्द बनाए रखने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया।

महाराष्ट्र के विकास पर पीएम मोदी से मिले सीएम फडणवीस

नई दिल्ली। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। इस महत्वपूर्ण बैठक की पुष्टि प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने एक पोस्ट और साझा की गई तस्वीरों के माध्यम से की। पीएमओ ने कहा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री फडणवीस ने खुद बैठक की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि उन्हें हमारे नेता और राष्ट्र के प्रिय प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर महाराष्ट्र के विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर उनका बहुमूल्य मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। सीएम फडणवीस ने प्रधानमंत्री मोदी को राज्य में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों और प्रमुख परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति और प्रगति से भी अवगत कराया। उन्होंने इस मुलाकात को हमेशा की तरह प्रेरणादायक बताया, जिससे उन्हें सकारात्मक ऊर्जा का संचार महसूस हुआ और उन्होंने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया।आलोचक, इस आधिकारिक बयान के अलावा, सूत्रों के अनुसार बैठक में महाराष्ट्र के कुछ अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा होने की संभावना है।

कर्नाटक में सताधारी कांग्रेस सरकार में बड़ा बदलाव

सिद्धारमैया ने सीएम पद से दिया इस्तीफा

बेंगलुरु। सिद्धारमैया ने गुरुवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, जिससे कांग्रेस में कई दिनों से चल रही खींचतान का अंत हो गया। सिद्धारमैया ने कहा कि कांग्रेस ने उन्हें पद छोड़ने के लिए कहा है ताकि उनके उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री पद पर पदोन्नत किया जा सके। यह घटनाक्रम सिद्धारमैया द्वारा कैबिनेट सहयोगियों के साथ नाशे पर हुई बैठक के कुछ ही घंटों बाद सामने आया है, जिसमें शिवकुमार भी उपस्थित थे, और जिसमें उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने का निर्णय लिया था।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कर्नाटक के राज्यपाल के विशेष सचिव प्रभु शंकर को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। राज्यपाल थावरचंद राहलोत, जो राज्य से बाहर हैं, आज रात लौट रहे हैं। सिद्धारमैया ने पत्रकारों से कहा कि मुझे विश्वास है कि राज्यपाल के वापस आने पर वे मेरा इस्तीफा स्वीकार कर लेंगे। उन्होंने कहा कि मैंने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया है, इससे पहले हाई कमांड ने मुझे इस्तीफा देने के लिए कहा था। मुझे पूरा विश्वास है कि राज्यपाल के आने पर वे इसे स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि संविधान के अनुसार ऐसा करना आवश्यक है।

उन्होंने आगे कहा कि हमारे पास पूर्ण बहुमत है। इसलिए, मुख्यमंत्री को सरकार बनाने की अनुमति देना संवैधानिक रूप से उचित है। मैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे का हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे यह अवसर प्रदान किया। सिद्धारमैया ने कहा कि कर्नाटक के लिए संवैधानिक तरीकों से नए मुख्यमंत्री का चुनाव करना होगा। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि मेरा मानना ​​है कि संविधान हमारा धर्म है और मतदाता हमारे देवता और भक्त हैं। मुझे दो बार मुख्यमंत्री बनने और दो बार विपक्ष का नेता बनने का मौका मिला।



राज्यपाल द्वारा इस्तीफे को स्वीकार करने या न करने के सवाल पर निवर्तमान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यपाल की भी कुछ संवैधानिक जिम्मेदारियां होती हैं जिनका उन्हें पालन करना चाहिए। कांग्रेस नेता ने कहा कि मैं एक गाँव से आया हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं विधायक, मंत्री या मुख्यमंत्री बनूँगा। राजनीति में मेरा प्रवेश संयोगवश हुआ। मेरे माता-पिता या मेरे परिवार का कोई भी सदस्य राजनीति से जुड़ा हुआ है। सिद्धारमैया ने आगे कहा कि मैं बुद्ध, अंबेडकर और बसवा के आदर्शों में विश्वास रखता हूँ। मैं संविधान में विश्वास रखता हूँ। मेरा मानना ​​है कि सभी जाति, धर्म और समुदायों को एक साथ रहना चाहिए। मेरा यह भी मानना ​​है कि धन का समान वितरण होना चाहिए। इसीलिए बुद्ध, बसवा, गांधी और अंबेडकर की शिक्षाएँ मेरी राजनीति की जड़ रही हैं... मेरा मानना ​​है कि एक समतावादी समाज होना चाहिए और सभी को समान अधिकार मिलने चाहिए।

इससे पहले मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के लोक भवन के लिए रवाना होते ही उनके आवास के बाहर हंगामा और विरोध प्रदर्शन की खबरें आईं। प्रदर्शनकारियों को कारों के काफिले को रोकने की कोशिश करते देखा गया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के आवास पर पहुंचने के बाद, राज्य मंत्री लक्ष्मी हेब्बलकर ने पत्रकारों से कहा कि कांग्रेस नेता केवल पार्टी के उच्च कमान के निर्देशों का

पालन कर रहे हैं। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि मैं पहले दिन से ही कर रही हूँ कि उच्च कमान जो भी कहेगा, न केवल मैं बल्कि हमारे मुख्यमंत्री भी उसका पालन करेंगे। वह वही कर रहे हैं जो उच्च कमान ने उन्हें बताया है।

कर्नाटक में कांग्रेस सरकार पूरी तरह विफल, युवा परेशान : बी.वाई. विजयेंद्र

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक बी.वाई. विजयेंद्र ने गुरुवार को कर्नाटक सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि राज्य में अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सिद्धारमैया के बाद अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। होसपेट में मीडिया से बातचीत के दौरान विजयेंद्र ने कहा, सिद्धारमैया के बाद मुख्यमंत्री कौन बनेगा, यह अब सबसे बड़ा सवाल बन गया है। उन्होंने कहा, कांग्रेस के तीन साल के शासन में कर्नाटक आर्थिक संकट में फंस गया है। सरकार ने लोगों को अच्छा शासन देने के लिए कोई ईमानदार और गंभीर प्रयास नहीं किया। राज्य की शासन व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार किसानों, गरीबों और युवाओं की समस्याओं को नजरअंदाज कर रही है और सिर्फ अल्पसंख्यकों को खुश करने पर ध्यान दे रही है।

उन्होंने कहा, सरकार किसानों, गरीबों और बेरोजगार युवाओं की समस्याएँ सुनने में विफल रही है। मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर चल रही लड़ाई शासन से भी बड़ा मुद्दा बन गई है। सत्ता की अंदरूनी खींचतान का असर प्रशासन पर पड़ रहा है। राज्य के युवा सरकार से नाराज हैं और कर्नाटक धीरे-धीरे ड्रग्स कैपिटल बनता जा रहा है।% सिद्धारमैया के इस्तीफे को लेकर चल रही चर्चाओं का जिक्र करते हुए विजयेंद्र ने कहा कि मुख्यमंत्री पद को लेकर कांग्रेस के अंदर अलग-अलग गुट सक्रिय हो गए हैं।

एक खाते में 4 नॉमिनी बने

बैंकों के लिए सिरदर्द

नईदिल्ली। बैंक खातों और लॉकर में एक से ज्यादा नॉमिनी होने से क्लेम सेटलमेंट में बढ़ती दिक्कों के बीच बैंकों ने अब भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से स्पष्ट और एक जैसे नियम बनाने की मांग की है। बैंक अधिकारियों का कहना है कि मौजूदा व्यवस्था में कई बार नॉमिनी अलग-अलग समय पर दावा पेश करते हैं, जिससे पैसे के भुगतान और प्रक्रिया पूरी करने में परेशानी बढ़ जाती है। फिलहाल नियमों के अनुसार एक बैंक खाते या लॉकर में अधिकतम चार लोगों को नॉमिनी बनाया जा सकता है लेकिन बैंकों का कहना है कि जब सभी नॉमिनी एक साथ बैंक नहीं पहुँचते या मामला अदालत में चल रहा होता है, तब क्लेम निपटाना काफी जटिल हो जाता है। बैंक अधिकारियों के मुताबिक, इस मुद्दे को अनौपचारिक तौर पर आरबीआई के सामने रखा जा चुका है और जल्द ही नई गाइडलाइंस की मांग की जाएगी।

कैम्बे बेसिन ऑयल ब्लॉक

पर कब्जे की जंग

नई दिल्ली। गुजरात के कैम्बे बेसिन में एक अहम ऑयल एंड गैस ब्लॉक (सीबी-ओएस-02) के कंट्रोल को लेकर सरकारी तेल कंपनी ओएनजीसी और प्राइवेट कंपनी वेदांता के बीच कानूनी खींचतान जारी है। सरकार ने इस ब्लॉक का कॉन्ट्रैक्ट वेदांता के लिए आगे बढ़ाने से मना कर दिया था और ओएनजीसी को इसकी कमान संभालने को कहा था। लेकिन वेदांता ने इस फैसले को अदालत में चुनौती दे दी है, जिसके चलते ओएनजीसी अब तक इस ब्लॉक का ऑपरेशनल कंट्रोल अपने हाथों में नहीं ले पाई है। इस पूरे विवाद की जड़ में प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट (पीएससी) है, जो सरकार और तेल कंपनियों के बीच होता है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 19 सितंबर 2025 को एक आदेश जारी करके इस ब्लॉक के कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाने से साफ इनकार कर दिया था।

भारत में ऊर्जा निवेश 170 अरब

डॉलर पर पहुंचने का अनुमान

नई दिल्ली। भारत में ऊर्जा क्षेत्र में निवेश 2026 में रिकॉर्ड 170 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। यह वृद्धि सौर ऊर्जा और तेल शोधन क्षेत्र के तेज विस्तार के दम पर हो रही है, क्योंकि देश बढ़ती ऊर्जा मांग को पूरा करने एवं स्वच्छ ऊर्जा की ओर बदलाव के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के प्रयास तेज कर रहा है। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की विश्व ऊर्जा निवेश 2026 रिपोर्ट के अनुसार, पिछले पांच वर्ष में भारत में ऊर्जा निवेश औसतन 11 प्रतिशत वार्षिक दर से बढ़ा है। इस दौरान सौर फोटोवोल्टिक (पीवी) में सालाना आधार पर निवेश 25 प्रतिशत और तेल शोधन में 23 प्रतिशत की दर से बढ़ा। ये दोनों क्षेत्र मिलकर कुल ऊर्जा व्यय में वृद्धि का लगभग एक-चौथाई हिस्सा रहे। रिपोर्ट में कहा गया कि शोधन क्षेत्र में तेज निवेश से भारत 2030 तक अपनी शोधन क्षमता में लगभग 15 प्रतिशत की वृद्धि करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

ग्लोबल मार्केट में सोने

में बड़ी गिरावट

नईदिल्ली। गुरुवार को सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अमेरिका और ईरान के बढ़ते तनाव के बीच डॉलर मजबूत हुआ और कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आ गई, जिस का असर गोल्ड पर पड़ा। इसी के चलते वैश्विक बाजार में सोना दो महीनों के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। स्पाट गोल्ड करीब 1.37% गिरकर 4,387 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच गया। जबकि अमेरिकी गोल्ड फ्यूचर्स में भी बड़ी गिरावट देखी गई। बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक, भू-राजनीतिक तनाव के बीच निवेशक फिलहाल सुरक्षित निवेश के तौर पर डॉलर को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट में आई इस गिरावट का असर भारतीय क्मोडिटी मार्केट में भी देखने को मिल सकता है। भारत में बकरीद के कारण आज एमसीएक्स पर सुबह का कारोबार बंद है।

गुजरात टाइटंस का सामना

आज राजस्थान रॉयल्स से होगा

मुम्बईपुर। आईपीएल 2026 के क्कालीफायर-2 की तस्वीर साफ हो गई है। शुक्रवार को मुम्बईपुर के यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में गुजरात टाइटंस का

सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। क्कालीफायर-1 में हारने के बाद गुजरात के पास फाइनल में पहुंचने का यह आखिरी मौका है। जबकि सनराइजर्स हैदराबाद को एलिमिनेटर में हराकर आ रही राजस्थान रॉयल्स के हौसले बुलंद हैं।

मुम्बईपुर का मैदान इस सीजन में दोनों टीमों के लिए बिल्कुल अलग अनुभव लेकर आया है। गुजरात टाइटंस के लिए यह मैदान अब तक अनलकी रहा है, जहाँ उन्हें ग्गप राउंड के मैच के साथ-साथ मुंबई इंडियंस के खिलाफ भी हार का सामना करना पड़ा था। वहीं राजस्थान रॉयल्स के हौसले इस मैदान पर बुलंद हैं, क्योंकि उन्होंने इसी पिच पर एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर शानदार जीत दर्ज की थी और क्कालीफायर-2 में कदम रखा है।

आईपीएल के प्लेऑफ मैचों में गुजरात टाइटंस का पलड़ा राजस्थान रॉयल्स पर हमेशा भारी रहा है। साल 2022 में गुजरात ने राजस्थान को प्लेऑफ में हराया था। बाद में फाइनल मैच में भी राजस्थान को ही हराकर आईपीएल ट्रॉफी जीती थी। गुजरात के लिए एक और बड़ी बात यह है कि क्कालीफायर-2 मैच में सबसे ज्यादा 129 रन बनाने का रिकॉर्ड भी उनके कप्तान शुभमन गिल के नाम है।

आईपीएल के इतिहास में अब तक सिर्फ एक ही बार ऐसा हुआ है जब एलिमिनेटर खेलने वाली टीम चैंपियन बनी हो। साल 2016 में सनराइजर्स हैदराबाद ने यह रिकॉर्ड बनाया था। इस बार राजस्थान रॉयल्स भी इसी इतिहास को दोहराने की कोशिश में है। अगर राजस्थान की टीम शुक्रवार को गुजरात टाइटंस को हरा देती है, तो उसे रविवार को फाइनल में आरसीबी से खेलना होगा।

ऊर्जा संकट और बढ़ते विदेशी मुद्रा संकट : मितव्ययिता की शुरुआत पहले हो जानी चाहिए थी!

राजकुमार सिंह

भारत की राजनीति हर चीज को राजनीतिक नजरिये से देखने-दिखाने को अभिशप्त है। ताजा उदाहरण गहराते ऊर्जा संकट और बढ़ते विदेशी मुद्रा संकट से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से अपील की कि पेट्रोल-डीजल की खपत कम करें और उसके लिए वर्क फ्रॉम होम, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग तथा कार पूलिंग जैसे उपाय करें। एक साल तक सोना न खरीदने और विदेश यात्रा से परहेज करने की अपील भी की गई है। अपील खाद्य तेलों का उपयोग 10 प्रतिशत घटाने की भी है।

अमेरिका और ईरान में संघर्ष विराम के बावजूद पश्चिम एशिया में जारी टकराव और अस्थिरता से कमोबेश पूरा विश्व ऊर्जा संकट झेल रहा है। तमाम देशों ने उससे निपटने के लिए अपनी परिस्थितियों के अनुरूप कदम

भी उठाए हैं। मंहगाई की मार और नागरिकों की दुश्गरियों की चर्चा के बावजूद दिखा नहीं कि किसी भी देश में विपक्ष ने सरकार के ऐसे कदमों की आलोचना की हो, लेकिन भारत में विपक्ष की प्रतिक्रियाओं से लगता है कि मानो मोदी सरकार ही इस संकट के लिए जिम्मेदार हो। चुनाव लोकतंत्र की प्राणवायु हैं, पर चुनाव जीत कर सत्ता में आने और उसे बनाए रखने की सोच कई बार राजनीतिक नेतृत्व को देखे हित में सही समय पर सही फैसले लेने से रोकती भी है। पड़ोसी देशों से लेकर दूरराज तक के देशों में पेट्रोल-डीजल के दाम मार्च में ही बेतहाशा बढ़ गए।

विकसित देश भी मंहगाई की मार से अछूते नहीं, लेकिन सात मार्च को कमर्शियल और घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में कुछ वृद्धि के अलावा इस मोर्चे पर हमारी सरकार मौन ही रही। विपक्ष द्वारा व्यक्त आशकाओं की



दरकिनार करते हुए देश में पर्याप्त भंडार का दावा कर सरकार देशवासियों को मंहगाई से बचाए रखने का भरोसा भी देती रही।

अतीत के अनुभव के मद्देनजर समझ पाना मुश्किल नहीं था कि सरकार की यह सदाशयता पांच राज्यों में मतदान तक ही है। हमने अतीत में भी देखा है कि सरकारी तेल कंपनियां चुनाव के दौरान अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम बढ़ जाने पर भी देश में कीमत नहीं बढ़ाती थीं, लेकिन मतदान

समाप्ति की शाम ही सारी कसर पूरी कर लेती थीं। उस लिहाज से मोदी सरकार ने ज्यादा धैर्य दिखाया।

जब अंतरराष्ट्रीय कारणों से वैश्विक संकट है तो झेलना पड़ेगा ही। हां, पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में मतदाताओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की आशंका के चलते ऐसे जरूरी कदम भी दो माह बाद उठाने के लिए सरकार की आलोचना की जा सकती है। अगर कारोना काल में बिना तामझाम सादगी से चुनाव हो सकते थे, तो

इस बार क्यों नहीं?

ऊर्जा संकटकाल में धुंआधार चुनाव प्रचार में फूँके गए पेट्रोल-डीजल की जवाबदेही किसकी है? शक्ति प्रदर्शन के रूप में हुए नई सरकारों के शपथ ग्रहण में तमाम बड़े नेता क्या कार पूल करके आए थे? शाश्वत समस्या है कि हमारी सरकारें आग

लगने पर ही कुआं खोदने की सोचती हैं।

अगर हम अपनी जरूरत के 80 प्रतिशत तक कच्चे तेल के लिए आयात पर निर्भर हैं, तब आज तक देश में विश्वसनीय और सुविधाजनक सार्वजनिक परिवहन तंत्र क्यों नहीं विकसित किया गया? कोरोना काल में किए गए वर्क फ्रॉम होम के प्रयोग को यथासंभव जीवन शैली का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। छोटे काफिले के साथ या मेट्रो में सफर कर प्रचार बटोरनेवाले नेता-अफसर ऐसा हमेशा क्यों नहीं कर सकते?

जो देश हरित क्रांति करने में सक्षम रहा, उसकी खाद्य तेल आयात पर निर्भरता सरकारी प्राथमिकताओं पर ही सवालिया निशान लगती है। कच्चे तेल के बाद सबसे ज्यादा हमारा आयात बिल सोने का है, पर बेलगाम कीमतों के चलते वह आम भारतीय की क्रयशक्ति से बाहर है, जबकि सक्षम लोगों पर किसी अपील का असर शायद ही हो।

